Website : www.kalamlok.com

वर्ष - 10 अंक - 139

बक्सर, रविवार 20 सितम्बर 2026

<7|

कलम लोक

पृष्ठ - 8
मूल्य 2 रू.

> यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे, तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में एनएसयूआई की हार से मचा घमासान, एबीवीपी ने चार में से तीन केन्द्रीय पद जीते

बागियों की जीत से टिकट बंटवारे पर सवाल; मतगणना रोकने के आरोपों ने बढ़ाई सियासी गर्मी

एनएसयूआई का खाता नहीं खुला; निर्दलीय दीपांशु शोकीन की बड़ी जीत के बीच कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया और एनएसयूआई ने मतगणना पर उठाए सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2026 के नतीजों के बाद कांग्रेस के छात्र संगठन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) में उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रक्रिया तक कई सवाल उठ रहे हैं। चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने केंद्रीय पैनल के चार में से तीन पदों पर जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे दीपांशु शोकीन ने जीत हासिल की। एनएसयूआई चारों प्रमुख पदों पर जीत दर्ज नहीं कर सकी।

चुनाव परिणाम के बाद एक तरफ संगठन से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रदर्शन ने टिकट बंटवारे की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं दूसरी तरफ एनएसयूआई और दिल्ली कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया, प्रचार के अवसर, लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन के इस्तेमाल और मतगणना की पारदर्शिता को लेकर आरोप लगाए हैं।

कन्हैया कुमार को जुलाई 2023 में एनएसयूआई के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रभारी नियुक्त किया गया था। डूसू चुनाव के बाद उनके कार्यकाल के दौरान उम्मीदवारों के चयन को लेकर पहले सामने आए विवादों का भी उल्लेख किया जा रहा है। 2024 के पंजाब विश्वविद्यालय चुनाव का उदाहरण दिया जा रहा है। उस चुनाव में एनएसयूआई के बागी अनुराग दलाल ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और 3,433 वोटों से जीत हासिल की थी। एनएसयूआई के आधिकारिक उम्मीदवार राहुल नैन को 501 वोट मिले थे और वह छठे स्थान पर रहे थे। इससे पहले चंडीगढ़ एनएसयूआई के तत्कालीन अध्यक्ष सिकंदर बूरा ने इस्तीफा दिया था। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अनुराग दलाल का समर्थन किया था और संगठन के नेतृत्व पर फैसला थोपने का आरोप लगाया था। इसके बाद संगठन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इसके लगभग एक साल बाद पंजाब विश्वविद्यालय में उम्मीदवार चयन को लेकर एनएसयूआई के भीतर एक और विवाद सामने आया। उस समय एनएसयूआई के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी चाहते थे कि सुमित कुमार को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया जाए, जबकि कन्हैया कुमार ने परबजोत सिंह गिल का समर्थन किया था। इसके बाद सुमित कुमार ने एनएसयूआई से अलग होकर चुनाव लड़ा। उन्हें 2,660 वोट मिले और वह दूसरे स्थान पर रहे, जबकि एनएसयूआई के उम्मीदवार को 1,359 वोट मिले। उस चुनाव में एबीवीपी के गौरव वीर सोहल ने 3,148 मतों से जीत दर्ज की थी।

डूसू में पिछले साल भी एनएसयूआई से जुड़ी बगावत देखने को मिली थी। एनएसयूआई की पूर्व नेता उमांशी लांबा को टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। उन्हें 5,522 वोट मिले थे। उस चुनाव में एबीवीपी के आर्यन मान ने 28,841 मतों से जीत दर्ज की थी, जबकि एनएसयूआई की उम्मीदवार जॉसलिन चौधरी को 12,645 वोट मिले थे। इस बार दीपांशु शोकीन की जीत के बाद पुराने मामलों का भी संदर्भ दिया जा रहा है। एनएसयूआई के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का पुराना चुनावी अनुभव भी इस चर्चा में शामिल किया जा रहा है।

निर्दलीय दीपांशु शोकीन की बड़ी जीत ने बढ़ाई चर्चा

उपाध्यक्ष पद का परिणाम डूसू चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। एनएसयूआई से टिकट के दावेदार रहे दीपांशु शोकीन ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और 30,615 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। एबीवीपी के इशू मौर्य को 16,910 वोट मिले, जबकि एनएसयूआई के आधिकारिक उम्मीदवार वीर छत्रथ को महज 4,313 वोट प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहे। वीर छत्रथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष छत्रथ के बेटे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दीपांशु शोकीन ने एनएसयूआई से टिकट मांगा था और शुरुआत में संगठन ने उन्हें नामित भी किया था, लेकिन बाद में उनसे अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। परिणाम में उन्हें एनएसयूआई के आधिकारिक उम्मीदवार से कई गुना अधिक वोट मिले। यही वजह है कि चुनाव के बाद एनएसयूआई में उम्मीदवार चयन और टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

एनएसयूआई के चारों प्रमुख पदों पर हार

डूसू चुनाव के केंद्रीय पैनल में एबीवीपी ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकीन के खाते में गया। इस तरह एनएसयूआई किसी भी केंद्रीय पद पर जीत हासिल नहीं कर सकी। एनएसयूआई के लिए स्थिति इसलिए भी चर्चा का विषय बनी क्योंकि उसके टिकट से वंचित रहे कुछ दावेदारों ने अलग होकर चुनाव लड़ा और प्रमुख पदों पर आधिकारिक उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि किसी चुनाव के परिणाम के पीछे केवल एक कारण को जिम्मेदार मानने के बजाय अलग-अलग उम्मीदवारों के प्रदर्शन और चुनावी परिस्थितियों को अलग-अलग देखना जरूरी है।

संयुक्त सचिव पद पर भी टिकट के दावेदार ने दी कड़ी टक्कर

संयुक्त सचिव पद के चुनाव में भी एनएसयूआई को इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा। विशेष यादव एनएसयूआई से टिकट के प्रमुख दावेदार बताए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, पहले उन्हें संयुक्त सचिव पद का टिकट देने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में उनका टिकट काट दिया गया। इसके बाद उन्होंने समाजवादी छात्र सभा के समर्थन से चुनाव लड़ा। विशेष यादव को 15,778 वोट मिले और वह दूसरे स्थान पर रहे। इस पद पर एबीवीपी के लक्ष्य राज सिंह ने 16,615 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। एनएसयूआई के आधिकारिक उम्मीदवार गोपाल चौधरी को 15,206 वोट मिले और वह तीसरे स्थान पर रहे। इस परिणाम ने भी संगठन के भीतर उम्मीदवारों के चयन को लेकर बहस को बढ़ा दिया है।

'छात्रों की गूंज' में सरकार पर गंभीर आरोप

सिस्टम ने पूरे देश को कब्जे में ले लिया : राहुल

सीएम मोहन यादव ने किया पलटवार

इंदौर (एजेंसी) कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' में केंद्र और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक ऐसा सिस्टम बन गया है, जिसने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया है और वह नहीं चाहता कि छात्र सवाल पूछें। उन्होंने कहा कि छात्र ही देश का भविष्य हैं और वही देश से नफरत को खत्म कर सकते हैं। उनके इस बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम को 'झूठ की गूंज' बताया और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े आंकड़े सामने रखे।

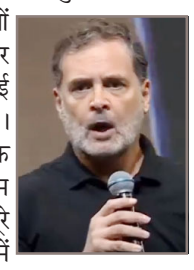

इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आए छात्रों ने अपनी समस्याएं और मुद्दे राहुल गांधी के सामने रखे। इनमें शिक्षा, सरकारी नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, आरक्षण और छात्र सुविधाओं से जुड़े विषय शामिल रहे। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र भारत का भविष्य हैं और उनके बिना कोई भी देश मजबूत नहीं बन सकता।

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि छात्र 'अदाणी, अंबानी और जय शाह' सहित व्यवस्था से जुड़े लोगों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार 'अंधभक्त' इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों में जिज्ञासा, प्रेम, विनम्रता, सहनशीलता और ईमानदारी जैसे गुण होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अनुसार केवल छात्र ही देश से नफरत को खत्म कर सकते हैं।

राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई आंकड़े भी बताए। उन्होंने दावा किया कि देश में शिक्षकों के 10 लाख पद रिक्त हैं और एक लाख स्कूल बंद हो गए हैं। उनके अनुसार, बंद हुए स्कूलों में 55 प्रतिशत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हैं।

राहुल गांधी ने शिक्षा बजट का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने बजट का 4.6 प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया था, जबकि अब यह घटकर 2.6 प्रतिशत या 7.7 लाख करोड़ रुपये रह गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत तथा उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी पर भी निशाना साधा और व्यवस्था को खराब करने का आरोप लगाया।

एलपीजी सिलेंडर पर सरकार का बड़ा ऐलान

1 अक्टूबर से इन ग्राहकों के लिए बदला नियम

नई दिल्ली (एजेंसी)। घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य पर घरेलू LPG रिफिल बुक कराने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं कराया तो सब्सिडी का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है।

बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि सब्सिडी वाली एलपीजी केवल वास्तविक और योग्य परिवारों तक पहुंचे। प्रत्येक कनेक्शन को आधार-प्रमाणित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का कॉमर्शियल और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए डायवर्जन रोकने में मदद मिलती है। इसके अलावा, डुप्लीकेट और अयोग्य कनेक्शन हटते हैं। वहीं, सब्सिडी पहुंचाने का तरीका पारदर्शी और सही लोगों तक पहुंचने वाला बनता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी वास्तविक परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है और प्रत्येक योग्य उपभोक्ता इसे कई आसान तरीकों से पूरा कर सकते हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि 19 सितंबर तक देश के 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता यानी 89.9 प्रतिशत अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं। इन उपभोक्ताओं को दोबारा प्रमाणीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें रिफिल पहले की तरह मिलता रहेगा।

सीएम रेखा की एज में गड़बड़ी, केजरीवाल का नाम लिंक नहीं...

दिल्ली में कई नेताओं को चुनाव आयोग से मिला नोटिस

नई दिल्ली (एजेंसी)। एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत विवरण में गड़बड़ी को लेकर जिन मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई अन्य नेताओं के नाम भी शामिल है। मुख्यमंत्री को उम्र से संबंधित गड़बड़ी और केजरीवाल को उनका नाम पुराने एसआईआर से लिंक नहीं होने के कारण नोटिस भेजा गया है। वहीं, आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर नाराजगी जताई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की मतदाता हैं। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से संबंधित प्रविष्टि को जनगणना प्रपत्र में प्रदान किए गए विवरणों के आधार पर तार्किक विसंगतियों की सूची में पाया गया।

भारत निर्वाचन आयोग की मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें नोटिस जारी किया गया और नामित बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए मान्य कर दिया गया है, जिसका आधिकारिक प्रकाशन 4 नवंबर को किया जाना है।

पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनके बेटे और माता पिता की प्रविष्टि में भी विसंगति मिली है। केजरीवाल व उनके स्वजन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। दिल्ली निर्वाचन अधिकारी के दस्तावेजों के अनुसार इस विधानसभा के पार्ट 51, के जी मार्ग के 110 मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें केजरीवाल के परिवार के पांच सदस्यों का नाम शामिल है।

आयोग ने बताया क्यों भेजा गया नोटिस?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की विसंगति मिलने पर 33 लाख से अधिक मतदाताओं को इस तरह के नोटिस जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य विवरण में मिलने वाली गलती को ठीक करने के लिए सत्यापन करना है। नोटिस जारी होने के बाद बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) मौके पर जाकर सत्यापन और मतदाता की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों व संबंधित तथ्यों की जांच करता है। मुख्यमंत्री को दिए गए नोटिस में भी यह प्रक्रिया अपनाई गई।

कैश का दबाव बना रहे व्यापारी

एमडीआर लागू होने से पहले ही यूपीआई लेन-देन में शुरू हो गई आनाकानी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 15 अक्टूबर से मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू होना है, लेकिन अभी से इसका विरोध होने लगा है। गाजियाबाद में व्यापारी यूपीआई से भुगतान लेने में आनाकानी करने लगे हैं तो झांसी में कुछ पेट्रोल पंपों ने यूपीआई से पेमेंट नहीं लेने की सूचना चस्पा कर दी है। हरियाणा के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर रात के समय स्कैनर व्यवस्था काफी कम कर दी गई है। मध्य प्रदेश के व्यापारियों ने 23 सितंबर को नो-यूपीआई दिवस मनाने का निर्णय लिया है। उस दिन वे यूपीआई से भुगतान नहीं लेंगे।

राजधानी दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में इसका कोई असर नहीं है, लेकिन, मध्य प्रदेश के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर विरोध दिखने लगा है। मध्य प्रदेश के 125 व्यापारी संगठनों ने शनिवार को इंदौर में बैठक कर 23 सितंबर को नो-यूपीआई दिवस मनाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि पेट्रोल पंप 16 अक्टूबर से दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि हमने अपने राज्य स्तरीय समन्वयक को भी पत्र लिखा है। झांसी में कुछ पेट्रोल पंपों पर यूपीआई के जरिये 2 हजार से अधिक का पेट्रोल-डीजल नहीं देने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। हालांकि झांसी पेट्रोल-डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव बब्बर का कहना है कि संगठन स्तर पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पंप पर लगी सूचनाएं संचालकों का व्यक्तिगत फैसला हो सकती हैं। गाजियाबाद में कुछ दुकानदारों ने ग्राहकों से नकदी की मांग करनी शुरू कर दी है।

यमन में 24 घंटे तक भीषण जंग, 44 लोगों की मौत

साना (एजेंसी)। यमन में सरकारी सुरक्षा बलों और हूती विद्रोही समूह के बीच पिछले 24 घंटों में हुई भीषण झड़पों में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई है। सैन्य सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच दक्षिण-पश्चिम ताइज़ और लहज प्रांतों के प्रमुख मोर्चों पर भारी संघर्ष और गोलाबारी जारी है।

ताइज़ प्रांत के अल-कधा और अल-वाज़िया क्षेत्रों में यमनी सरकारी बलों ने हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए कई हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। इस दौरान हुई हिंसक झड़पों में 6 सरकारी सैनिक और 11 हूती लड़ाके मारे गए। दूसरी ओर, हूती सैन्य सूत्र ने जानकारी दी है कि कहबूब क्षेत्र में बीते 24 घंटों की लड़ाई में एक कमांडर सहित 15 हूती लड़ाके मारे गए हैं।

हालिया हिंसा से पहले चालू माह की शुरुआत में हूती समूह ने यमन के दक्षिण-पश्चिमी लाल सागर तट पर महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की थी।

सम्राट चौधरी का ऐलान

बिहार में 10 हजार उद्योग लगेंगे, 12 लाख प्रवासियों को वापस लाएगी सरकार

पटना (एजेंसी)।

बिहार में सम्राट सरकार बड़े पैमाने पर उद्योग-धंधे लगाने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि अगले 5 सालों में राज्य के अंदर लगभग 10 हजार उद्योग लगाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि बिहार के लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। उन्हें बिहार में ही रोजगार दिलाया जाएगा। इसके लिए उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत, प्रवासी मजदूरों को बिहार वापस लाया जाएगा।

सीएम सम्राट चौधरी ने शनिवार को पटना के तारामंडल में सेवा संकल्प अभियान के तहत राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नेशनल इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का लोकार्पण किया। साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी कार रैली के तहत 25 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में औद्योगिक माहौल तैयार हो चुका है और अब तक करीब एक हजार उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। अगले पांच वर्षों में 10 हजार उद्योगों को बिहार की धरती पर स्थापित करने का लक्ष्य है। सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के बाहर यहां के 12 लाख लोग मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के बाहर कोई मजदूरी करने ना जाए। इसके लिए उद्योगों और उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। युवा उद्यमी नए स्टार्टअप के साथ बिहार की दिशा बदल सकते हैं। राज्य सरकार उनके प्रयासों को हरसंभव सहयोग देगी। बिहार टेक पोर्टल फॉर इनोवेशन इन आईटी सेक्टर के माध्यम से आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण विकास का महत्वपूर्ण आधार है। समृद्ध बिहार बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार ने एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सीएम चौधरी ने कहा कि बिहार को समृद्ध बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। युवा ऊर्जा, तकनीकी क्षमता और उद्यमशीलता को एक साथ जोड़कर राज्य को तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य ऐसा बिहार बनाना है, जहां सेवा के साथ नवाचार, रोजगार और उद्योग के नए अवसर लगातार उपलब्ध हों।

अब डोनाल्ड ट्रंप के पाले में गेंद

अमेरिका से युद्ध खत्म होने की तीन शर्तें, ईरान ने की बातचीत की पहल

तेहरान (एजेंसी)। ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध का अंत करने की पहल की है। इसके लिए उसने तीन शर्तें रखी हैं। इसके साथ ही अब गेंद अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाले में चली गई है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रजाई ने शनिवार को कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने और जंग के खात्मे के लिए अपनी शर्तें भेजने की पुष्टि की है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार रजाई ने एक मीडिया संगठन को दिए साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका को जल्द ही इन शर्तों पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा।

कतर के जरिए अमेरिका को भेजी गई तीन मुख्य शर्तें इस तरह से हैं। इसके तहत, सभी मोर्चों पर जारी सैन्य संघर्ष और युद्ध पर पूर्ण विराम। अमेरिका द्वारा जब्त सभी ईरानी संपत्तियों को बहाल करना। इसके अलावा ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी को तुरंत हटाना शामिल है।

रजाई ने स्पष्ट किया कि अमेरिका और इजरायल के आक्रामक कदम ईरान को 'परमाणु अप्रसार संधि' से बाहर निकलने का आधार प्रदान करते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि ईरान ने अभी तक एनपीटी छोड़ने का अंतिम निर्णय नहीं लिया है और यह पूरी तरह अमेरिका के आचरण पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान वर्तमान में सामूहिक विनाश के हथियारों पर रोक लगाने वाले फतवे और अपने परमाणु सिद्धांत पर कायम है, लेकिन भविष्य की गारंटी नहीं दी जा सकती।

ललन सिंह नाराज नहीं, अनंत सिंह और नीरज का झगड़ा सुलझाएगी जदयू; अब संजय झा ने संभाला मोर्चा

पटना (संवाददाता)। बिहार विधान परिषद के चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में घमासान छिड़ा हुआ है। जदयू के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह और पटना स्नातक सीट से एमएलसी नीरज कुमार के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बीच, पटना में हुए जदयू के प्रबोधन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की गैरमौजूदगी से भी सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि, अब पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने खुद मोर्चा संभाला और उन्होंने शनिवार को दावा किया कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि नेताओं में कोई मतभेद नहीं है। संजय झा ने ललन सिंह की पार्टी से चल रही नाराजगी की अटकलों को भी खारिज किया। साथ ही यह भी कहा कि अनंत और नीरज के मामले को पार्टी के वरीय नेता देख रहे हैं, जल्द ही इसका रास्ता निकाल लिया जाएगा।

दरअसल, अनंत सिंह और नीरज कुमार दोनों एक-दूसरे के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। अनंत सिंह ने शनिवार को कहा कि नीरज कुमार के कारण ही उन्हें जदयू छोड़नी पड़ी थी और मोकामा से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ा, फिर लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में जाना पड़ा। जबकि, उन्हें नीतीश कुमार से कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने नीरज कुमार को आगामी एमएलसी चुनाव में जीत-हार को लेकर 20 करोड़ की बाजी लगाने की चुनौती भी दे दी। अनंत ने कहा कि अगर वे बड़ा पहलवान हैं तो बताएं हार के बाद क्या करेंगे? वहीं, ललन सिंह की कथित नाराजगी की अटकलों को संजय झा ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जदयू के

नीरज की अनंत सिंह को चुनौती

इसके बाद, नीरज कुमार ने भी अनंत सिंह पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने बगैर नाम लिये अनंत सिंह को बेऊर जेल का संत बताया और आरोप लगाया कि वे अपराधियों और वारंटियों के साथ घूम रहे हैं। उनके आस-पास फरारी लोग हैं। नीरज ने दावा किया कि उन्होंने सबका विवरण नाला है। अनंत सिंह उन्हें बचा नहीं पाएंगे।

संजय झा ने संभाला मोर्चा

नेताओं की लगातार बयानबाजी और अटकलों से जदयू में घमासान की चर्चाओं के बीच पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने शनिवार को मोर्चा संभाला। उन्होंने एक चैनल से बातचीत में कहा कि पार्टी में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। अनंत और नीरज के झगड़े पर उन्होंने कहा कि पार्टी में यह सब होता रहता है, बर्तन बजते रहते हैं। पार्टी के वरीय नेता इस पर नजर बनाए हुए हैं। जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा।

ललन बोले- जदयू में कोई मतभेद नहीं

दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी शनिवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जदयू में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। शुक्रवार को पटना में हुए प्रबोधन कार्यक्रम में अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा कि उनका गुजरात में कार्यक्रम था, इसलिए वे वहां पर थे। ललन सिंह ने कहा कि वह साधारण कार्यक्रम था, उसमें जदयू के सभी विधायक और एमएलसी को बुलाया गया था। इसलिए उन्हें उस बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि, उन्होंने अनंत सिंह और नीरज के मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

नेता नीतीश कुमार हैं और उनके बाद अन्य सीनियर नेता आते हैं। ललन सिंह पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और वरीय नेताओं में से एक हैं। इस लिहाज से पार्टी में कोई भी नीतिगत फैसला होता है, तो उनसे पूछकर ही सब निर्णय लिए जाते हैं।

पर्युषण पर्व : चौथे दिन 'उत्तम शौच धर्म' की पूजा-अर्चना

पटना (संवाददाता)। अखिल भारतीय दिगम्बर जैन महासमिति की ओर से आयोजित 10 दिवसीय दसलक्षण (पर्युषण) पर्व के चौथे दिन शनिवार को श्रद्धालुओं ने 'उत्तम शौच धर्म' की पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर पटना के मीठापुर, कदमकुआं, मुरादपुर, कमलदह, गुरारा एवं कालीबीबी का कटरा स्थित दिगम्बर जैन मंदिरों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भगवान का अभिषेक एवं शांतिधारा का आयोजन किया गया।? महासमिति के महामंत्री एमपी जैन ने बताया कि कदमकुआं स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में ऐलक 105 श्री गोसल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में पर्युषण पर्व का आयोजन हो रहा है। पूजा का सम्पादन भोपाल से पधारे प्रतिष्ठाचार्य पंडित अनिल शास्त्री भैयाजी तथा संगीतमय प्रस्तुति सागर के प्रसिद्ध भजनकर्ता एवं संगीतकार रवि जैन द्वारा किया गया।

डीयू छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी की सफलता पर सरावगी ने जताई खुशी

पटना(संवाददाता)। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की सफलता पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी है। शनिवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि डीयू छात्रसंघ के चार केंद्रीय पदों में से तीन पर एबीवीपी की जीत युवाओं के बीच उसकी विचारधारा और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों की स्वीकार्यता को दर्शाती है। कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने मत से छात्र राजनीति में सकारात्मक सोच, अनुशासन, शिक्षा और राष्ट्रनिर्माण से जुड़े मुद्दों को महत्व दिया है।

दीया का वीडियो बनाने पर पिटाई, फिर घर आकर धमकी

12 साल के प्रिंस ने तेजस्वी को बताया पूरा वाकया

पटना (संवाददाता)। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपने आवास में प्रिंस कुमार नाम के एक 12 साल के बच्चे से मुलाकात की। प्रिंस ने तेजस्वी से बातचीत में आरोप लगाया कि वह गुरुवार को पटना के मरीन ड्राइव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम का वीडियो बनाने गया था। वहां पर कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। बच्चे का यह भी आरोप है कि अगले दिन पुलिस ने घर आकर उसे धमकी दी। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम के दौरान रोते हुए पिटाई का आरोप लगा रहा था।

प्रिंस कुमार ने तेजस्वी यादव को पूरा वाकया सुनाते हुए कहा कि वह पटना के दीघा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने कहा, 'मैं दीया कार्यक्रम का वीडियो बना रहा था। दिखा रहा था कि इतना तेल बर्बाद हो गया। इससे पूरा गांव के लोग पूड़ी तल के खा लेते। तभी भाजपा कार्यकर्ता सब आया। उन्होंने पूछा कि वीडियो क्यों बना रहे हो। कैमरा बंद नहीं किया तो रॉड और डंडा निकालकर मारकर रेलिंग के उधर फेंक दिया। फिर पुलिस-प्रशासन आया और हम को पकड़कर ले गया।' तेजस्वी यादव ने प्रिंस से बातचीत के बाद बयान जारी कर भाजपा और एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रिंस भाजपा सरकार के आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम का वीडियो बना रहा था। तभी कथित तौर पर भाजपा के लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। फिर सड़क की रेलिंग से उसे नदी के पास फेंक दिया।

पुलिसकर्मी पर भी गंभीर आरोप

बच्चे के बयान आधार पर तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि भीड़ इकट्ठी होने के बाद पुलिस बच्चे और पिटाई करने वाले युवक को अपने साथ थाने ले गई। थाने ले जाकर युवकों को छोड़ दिया गया, लेकिन नाबालिग बच्चे को वहीं पर रखा गया। बाद में थाने से छोड़े जाने के बाद बच्चा घर पहुंचा, तो अगले दिन सुबह पुलिस आ धमकी और 12 साल के मासूम को धमकाने लगी। उस पर बयान बदलने का दबाव भी बनाया गया। प्रिंस का कहना है कि पुलिस अधिकारी ने उसे कथित पिटाई करने वाले युवकों को अपना दोस्त बताने के लिए कहा था, नहीं तो उसे नुकसान उठाने की धमकी दी।

विश्वकर्मा पूजा जुलूस में 2 मौत पर बवाल; भीड़ ने ट्रक जलाया, पुलिस पर पथराव, सड़क जाम

पटना (संवाददाता)। बिहार के सासाराम में विश्वकर्मा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान भीषण हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और पांच लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया और मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव में दो सिपाही चोटिल हो गए। शुक्रवार रात की घटना के विरोध में शनिवार को स्थानीय लोगों ने डेहरी-रोहतास रोड को घंटों तक जाम रखा। हादसा अमझौर थाना इलाके के रामडिहरा गांव की है

जानकारी के मुताबिक गांव में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर प्रतिमा की स्थापना की गई थी। शुक्रवार की शाम को ट्रैक्टर पर प्रतिमा को लेकर ग्रामीण विसर्जन के लिए सोनभद्र नदी की ओर जा रहे थे। रास्ते में एनएच 119 पर एक बेकाबू डंपर ट्रक ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दिया। ट्रैक्टर पर कई लोग सवार थे और पीछे विसर्जन में शामिल लोग चल रहे थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आशीष शर्मा और अजीत चंद्रवंशी नाम के दो युवकों की मौत हो गई और पांच लोग जख्मी हो गए। भीड़ ने ट्रक को घेर लिया। इसी बीच ड्राइवर और खलासी भीड़ के बीच अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल में पहुंचाया।

कस्तूरबा गांधी स्कूल में लटकी मिली 9वीं की छात्रा, छुट्टियों से हॉस्टल लौटते ही सुसाइड

सीतामढ़ी (संवाददाता)। बिहार के सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र स्थित रेवासी पंचायत के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शनिवार को 9वीं की एक छात्रा का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। घटना विद्यालय की ऊपरी मंजिल पर हुई, जहां छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलती मिली। सूचना मिलते ही विद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए। मृत छात्रा की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के फेनहारा थाना क्षेत्र के फेनहरा गांव निवासी रामनंदन सहनी की पुत्री रजनी कुमारी के रूप में हुई है।

रजनी विद्यालय में नौवीं कक्षा की छात्रा थी। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस के साथ एएसपी सह सदर एसडीपीओ आशीष आनंद, एसडीएम आनंद कुमार और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार रजनी का करीब एक महीने पहले ही स्कूल में एडमिशन कराया गया था। हाल ही में चौरचन पर्व पर वह घर गई थी और शनिवार को अपनी बुआ शकुंतला देवी के साथ स्कूल लौटी थी। उसकी छोटी बहन चुलबुल कुमारी का भी करीब 15 दिन पहले इसी विद्यालय में नामांकन कराया गया था। परिजनों के अनुसार रजनी दुर्गापूजा के दौरान घर जाने की बात कह रही थी। बताया जाता है कि उसकी बुआ विद्यालय परिसर में छोटी बहन से बातचीत कर रही थीं, तभी छात्रा के फंदे से लटके होने की सूचना मिली।

हॉस्टल में रहने की नहीं थी इच्छा : पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई है कि छात्रा विद्यालय के हॉस्टल में रहना नहीं चाहती थी। हालांकि उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। मृतका के माता-पिता हरियाणा में मजदूरी करते हैं, जबकि उसकी देखरेख की जिम्मेदारी स्थानीय अभिभावक के रूप में बुआ और फूफा निभाते थे।

एसडीपीओ ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया है, जिसने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और पूछताछ के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच सभी संभावित पहलुओं से की जा रही है।

पुलिस क्या बोली?

एसडीपीओ आशीष आनंद ने बताया कि वार्डन ने जानकारी दी कि करीब 1 महीने पूर्व रजनी का नामांकन विद्यालय में कराया गया था। वह चौरचन पर्व में अपने घर गई थी। शनिवार को स्थानीय अभिभावक बुआ और फूफा दोनों विद्यालय में पहुंचाने आए थे। विद्यालय में छोड़ने के कुछ ही देर बाद विद्यालय की एक अन्य छात्रा ने उसे फंदे से झूलता देखा और इसकी सूचना दी।

वार्डन से मांगी गई पूरी रिपोर्ट : डीईओ

जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि वार्डन को घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। हॉस्टल में रह रही अन्य छात्राओं में किसी तरह का भय न हो, इसके साथ ही उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि मामले में विभागीय दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा रही है। घटना की आगे की जांच पुलिस कर रही है।

डेंगू विस्फोट?

पटना में 18 दिनों में मिले 103 मरीज, हर दिन 10-15 हो रहे बीमार; कंकरबाग का बुरा हाल

पटना (संवाददाता)। बिहार में डेंगू ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी पटना में अगस्त में जहां डेंगू के 97 नए मरीज मिले थे, वहीं सितंबर में महज 18 दिनों में ही नए मरीजों की संख्या सौ के पार पहुंच गई है। तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की चिंता बढ़ा दी है। 31 अगस्त तक पटना में इस साल डेंगू के कुल 167 मरीजों की पुष्टि हुई थी। वहीं, अब यह संख्या बढ़कर 270 हो गई है। सिविल सर्जन कार्यालय के मुताबिक, अभी हर दिन 10 से 15 डेंगू मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। जनवरी से जून तक पटना में डेंगू के 44 मरीज मिले थे। जुलाई में 26 नए मामले सामने आए। अगस्त में संक्रमण की रफ्तार तेज हुई और महीने के अंत तक 97 नए मरीज मिल चुके थे। सितंबर के 18 दिनों में ही 103 नए मरीजों की पहचान हो चुकी है।

सिविल सर्जन डॉ. योगेन्द्र प्रसाद मंडल ने बताया कि सरकारी अस्पतालों के साथ - साथ निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब में जांच के दौरान भी डेंगू मरीजों की पहचान हो रही है। आंकड़ों के अनुसार, कुल मामलों का बड़ा हिस्सा निजी स्वास्थ्य संस्थानों में जांच के दौरान सामने आया है। बताया कि नगर निगम के सहयोग से प्रभावित इलाकों में फॉगिंग और एंटी-लार्वा अभियान चलाया जा रहा है। डेंगू मरीज मिलने वाले क्षेत्रों में मच्छरों के प्रजनन स्रोतों की जांच कर लार्वीसाइडल छिड़काव भी किया जा रहा है।

सनसनीखेज कांड

प्रेमिका के घर पीट-पीटकर प्रेमी की हत्या; मां और भाई समेत गर्लफ्रेंड गिरफ्तार

पटना(संवाददाता)। बिहार के शिवहर जिले में प्रेम प्रसंग में प्रेमी युवक की पीट-पीटकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना पिपराही थाने के अंबा उत्तरी (अंबा कला) गांव की है जहां देर रात युवक ललन कुमार (20) की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। ललन गांव के भरत साह का पुत्र था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमिका, उसके भाई और मां को गिरफ्तार कर लिया है।

लोगों ने बताया कि ललन को झांसा देकर घर बुलाया गया। देर रात वह युवती से मिलने उसके घर गया था। इसकी जानकारी मिलने पर युवती के परिजनों और अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया। आरोप है कि लाठी-डंडे और लोहे की खंती से उसकी पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पिपराही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के भाई विजय साह के आवेदन पर नौ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले में शांति देवी, उनके पुत्र आदित्य कुमार और पुत्री शिवानी कुमारी को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। थानाध्यक्ष उमाकांत सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग में मारपीट और हत्या का प्रतीत होता है। प्राथमिकी में नामजद तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने घटना स्थल से दो मोबाइल,घटना में प्रयुक्त लोहे की खंती तथा खून लगा लकड़ी का डंडा बरामद किया गया है। डीएसपी इशानी सिन्हा ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस कांड में कुछ अन्य लोगों का हाथ हो सकता है उनकी पहचान की जा रही है। डीएसपी ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से छानबीन करते हुए कांड का उद्भेदन किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई जानकारियां मिली हैं जिन पर पुलिस काम कर रही है। बताया जाता है कि ललन कुमार का अपने गांव की एक युवती शिवानी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के परिजनों को जब पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। दोनों एक ही समाज और गांव से ताल्लुक रखते हैं। समझाने पर जब वे नहीं माने तो ललन की हत्या की साजिश रच दी गई। 16 सितम्बर की रात को ललन को शिवानी के मोबाइल से कॉल करके मिलने के लिए बुलाया गया। देर रात जब वह शिवानी के घर पहुंचा तो पहले से तैयार बैठे लोगों ने लोहे की खंती और लाठी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। ज्यादा चोट लगने से उसकी मौत हो गई।

यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ सवर्ण सड़क पर उतरे

एससी-एसटी एक्ट में बदलाव की मांग; एनएच 319 ए दो घंटे जाम

कैमूर (संवाददाता)। बिहार के कैमूर जिले में नए यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ सवर्ण सड़क पर उतर गए। रागमढ़ के दुर्गा चौक पर शनिवार को सवर्ण महाआक्रोश मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सवर्ण समाज ने यूजीसी रेगुलेशन को वापस लेने और एससी-एसटी एक्ट में संशोधन की मांग की। सैकड़ों की संख्या में मोहनियां-चौसा नेशनल हाईवे 319ए को जाम कर दिया।

हाईवे पर लगभग दो घंटे तक प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आवागमन बाधित रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इससे वाहन चालक एवं राहगीर परेशान नजर आए। मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नया यूजीसी नियम समाज में वैमनस्य फैलाने वाला है। सरकार सवर्ण समाज के हितों की अनदेखी कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसे और प्रदर्शन होंगे।

सभा के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में थाना से लेकर जीबी कॉलेज तक रोड मार्च किया। संचालन भूपेंद्र सिंह ने किया। सभा को प्रशांत तिवारी, चुन्ना सिंह, गुड्डू सिंह, सहदेव सिंह, कमेश्वर सिंह, सुभाष सिंह, अभिमन्यु सिंह, रमेश पांडे, सुमीर सिंह राठौर, वीर बहादुर सिंह, राजेश सिंह, राजू सिंह, बंटी राजपूत, सुनील सिंह, धनंजय सिंह, अजय बिहारी राय, सुनील सिंह, रमेश सिंह, वीर बहादुर सिंह, नित्यानन्द उर्फ प्रिंस सिंह ने संबोधित किया।

'निशांत-सम्राट के खिलाफ जा रहे अनंत सिंह', नीरज ने बाहुबली MLA को दिया सीधा चैलेंज

पटना (संवाददाता)। बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) में दो नेताओं की सार्वजनिक लड़ाई से सियासत गर्माई हुई है। मोकामा से बाहुबली जदयू विधायक अनंत सिंह और पटना स्नातक सीट से जदयू एमएलसी नीरज कुमार एक-दूसरे पर छींटाकशी करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब जदयू प्रवक्ता नीरज ने अनंत सिंह को एमएलसी चुनाव लड़ने का सीधा चैलेंज कर दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अनंत सिंह, जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व के खिलाफ जा रहे हैं।

जदयू प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार ने शनिवार को एक बार फिर मोकामा से पार्टी के विधायक अनंत सिंह पर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अनंत सिंह, निशांत के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। निशांत जदयू के नेता हैं। निशांत को चुनौती देकर अनंत सिंह दूसरी पार्टी में घूस रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'अनंत सिंह खुलकर मैदान में आएं और बोलें कि वह स्वास्थ्य मंत्री निशांत एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के फैसले के खिलाफ हैं। वह (अनंत सिंह) कम पढ़े-लिखे हैं। एमएलसी चुनाव के बारे में नहीं जानते। वे पोलिंग एजेंट बनकर मतदान केंद्र पर भी नहीं जा सकते हैं।' नीरज ने आरोप लगाया कि अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को भी अपमानित किया है। वह अपनी पत्नी और मां-बाप क भी नहीं हो सके, तो किसके होंगे।

मंदिर में बहस को तैयार- नीरज कुमार

इससे पहले अनंत सिंह ने नीरज को बजरंग बली के मंदिर में आकर हनुमान जी के सामने बहस की चुनौती दी थी। इस पर नीरज ने पलटवार करते हुए कहा कि अनंत मंदिर जाने के लायक भी नहीं हैं। उनकी अकेले रोड पर चलने की हिम्मत भी नहीं है।

'एमएलसी बनाने में कोई योगदान नहीं'

नीरज ने स्पष्ट किया कि पिछले विधान परिषद चुनावों में उन्हें एमएलसी बनाने में अनंत सिंह का कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह ने अगर सहयोग किया होता, तो वह उनके प्रस्तावक होते। मगर वे प्रस्तावक बनने के लायक भी नहीं हैं। नीरज ने यह भी चेतावनी दी है कि वह कोर्ट के आदेशों की कॉपी निकलवा रहे हैं। वह अनंत सिंह को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा, 'हमको जो छेड़ता है, उसको इंजेक्शन देते हैं तो आह निकल जाती है।'

नीरज के खिलाफ अनंत सिंह

दरअसल, पटना स्नातक एमएलसी सीट पर आगामी चुनाव में अनंत सिंह, नीरज कुमार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने निर्दलीय दावेदारी कर रहे अनुज सिंह का समर्थन कर दिया है। दूसरी ओर, तीन बार के जदयू एमएलसी नीरज कुमार फिर से इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी से उनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है लेकिन मगर अनंत सिंह की आपत्ति से जदयू में घमासान छिड़ा हुआ है। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव अगले महीने होने की संभावना है। नवंबर में आठों सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें शिक्षक कोटे की चार और स्नातक कोटे की चार सीटें शामिल हैं।

एसपी भानु प्रताप की पत्नी फिर आईजीआई एमएस में भर्ती

पटना (संवाददाता)। खगड़िया एसपी और आईपीएस अधिकारी भानु प्रताप सिंह की पत्नी पूजा एक बार फिर आईजीआईएमएस में भर्ती है। उन्हें अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। इस दौरान वह अपनी बच्ची को वापस दिलाने की जिद रहीं। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक महिला का कहना था कि उन्हें लंबे समय से परेशान किया जा रहा है और उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने भानु प्रताप सिंह पर भी परेशानी का आरोप लगायाद्य भानु प्रताप की पत्नी लगातार बच्ची को लेकर अपनी मांग दोहराती रहीं। उनका आरोप है कि उन्हें अपनी बच्ची से दूर रखा जा रहा है और बच्ची से मिलने के लिए भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दे कि भानु प्रताप सिंह और उनकी पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद पिछले कुछ समय से चर्चा में है। पत्नी पहले भी आरोप लगा चुकी हैं कि उन्हें उनकी बेटी से दूर रखा गया। उन्होंने पति और ससुराल पक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। विवाद के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद आईजीआईएमएस में इलाज कराने की बात भी सामने आई थी.

जेन जी पर चिराग पासवान का फोकस बढ़ा, पटना में 24 सितंबर को लोजपा का बड़ा यूथ इवेंट

पटना (संवाददाता)। लोजपा-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग बिहार में बड़ा यूथ इवेंट करने जा रहे हैं। इसमें वह युवाओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। लोजपा-आर का ऐसा यह पहला कार्यक्रम माना जा रहा है, जिसमें सिर्फ युवाओं, खासकर जेन जी आबादी को साधा जाएगा।

लोजपा-आर के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान का यूथ इवेंट 24 सितंबर को पटना के वेटनरी ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इसका नाम 'यूथ बोले तो' कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को अपनी बात खुलकर रखने के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना है।

सुरेंद्र विवेक के अनुसार, यूथ इवेंट में युवा शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता, तकनीक, डिजिटल युग की चुनौतियों और अपने भविष्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चिराग पासवान के साथ सीधे संवाद कर सकेंगे।

राजेंद्र पुल पर काम से 21 से ट्रेनों के परिचालन में बदलाव

पटना (संवाददाता)। राजेंद्र पुल पर डबल लाइन वाले नए पुल को जोड़ने और दिनकर ग्राम सिमरिया-बरौनी के बीच मुख्य लाइन से कनेक्शन का काम शुरू होने के कारण 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। इस दौरान प्री-एनआई और एनआई कार्य के चलते कई ट्रेनों का आंशिक प्रारंभ और आंशिक समापन किया जाएगा। यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि इस अवधि में पटना, बरौनी, सहरसा, ललितग्राम, कटिहार, दानापुर, जसीडीह और मोकामा से चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन निर्धारित स्टेशन के बजाय बीच के स्टेशनों से किया जाएगा। इनमें कुछ ट्रेनें सोनपुर, बरौनी, मोकामा और किऊल से आंशिक रूप से शुरू या समाप्त होंगी। तीन अक्टूबर को पटना-झाझा ट्रेन को 30 मिनट नियंत्रित कर चलाया जाएगा। भागलपुर-आनंद विहार टर्मिनल और गोड्डा-राजेंद्र नगर की एक-एक ट्रेन को तीन घंटे पुनर्निर्धारित कर चलाया जाएगा।रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि 21 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच यात्रा करने से पहले ट्रेन के निर्धारित प्रारंभिक और अंतिम स्टेशन की जानकारी अवश्य ले लें, ताकि स्टेशन बदलने के कारण परेशानी न हो।

शादी के एक माह में ही प्रीति को मार दिया

पति और सास को उम्रकैद; 75-75 हजार जुर्माना भी

पूर्णिया (संवाददाता)। बिहार के पूर्णिया में शादी के बाद शुरू हुआ रिश्ता महज एक महीने में ही हत्या पर आकर खत्म हो गया। विवाहिता की इस हत्या के मामले में जिला व अपर सत्र न्यायाधीश शेमा एरम की अदालत ने पति दिलखुश कुमार और सास कुंती देवी को उम्रकैद की सजा दी। साथ ही अलग-अलग धाराओं में 75-75 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया।

मामला सरसी थानाक्षेत्र के बालू टोल वार्ड नंबर तीन की है। इस गांव में 16 अगस्त 2025 को मधेपुरा जिल के पुरैनी थानाक्षेत्र स्थित औराय गांव निवासी सकीचन साह की पुत्री प्रीति कुमारी की हत्य कर दी गई थी। इस हत्या को लेकर सरसी थाने में कांड संख्या 152/25 के तहत प्राथिमकी दर्ज करायी गई थी। । मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हरे राम ठाकुर ने अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने हत्या के साथ साक्ष्य छिपाने के मामले में भी दोनों को दोषी ठहराया गया। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपितों को केंद्रीय कारा, पूर्णिया भेज दिया गया।

प्राथमिकी के अनुसार प्रीति की शादी के बाद प्रीति अपने ससुराल चली गई। महज एक महीने बाद ही मायके वालों को गांव के लोगों के माध्यम से सूचना मिली कि प्रीति की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने के बाद उसके पिता और अन्य परिजन बेटी के ससुराल पहुंचे। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि वहां पहुंचने पर घर के लोग मौके से गायब थे। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और मृतका के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई। उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की।

प्रीति की हत्या उसके पति दिलखुश कुमार और सास कुंती देवी ने मिलकर की। आरोप था कि दोनों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद साक्ष्य छिपाने का भी आरोप लगाया गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाह और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए।

एकअन्य मामले में रौटा थानाक्षेत्र के पुरानी हाट में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या को लेकर जिला व अपर सत्र न्यायाधीश इनाम खान की अदालत ने पति मंटु हरिजन और सास फुलझाड़ी देवी को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अलग से दोनों को पांच-पांच हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। इस मामले को लेकर रौटा थाना कांड संख्या 276/25 दर्ज किया गया था। इस मामले में डगरूआ थानाक्षेत्र के सौरा जाबर निवासी चंदन राय की पुत्री अनामिका कुमारी की हत्या कर दी गई थी।

मृतका की मां लक्ष्मी देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इस मामले की खास बात यह रही कि आरोप गठन होने के महज पांच महीने में ही सुनवाई पूरी कर अदालत ने फैसला सुना दिया।

दशहरा-छठ में घर आने पर संकट, बस-प्लेन किराए में लगी आग; बिहार की प्रमुख ट्रेनों की स्थिति जान लें

मुजफ्फरपुर (संवाददाता)। दशहरा, दीपावली और छठ में घर आने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन में आरक्षित सीटों की मारामारी शुरू हो गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, पुणे और हैदराबाद से पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत बिहार के तमाम स्टेशनों पर पहुंचने वाली ट्रेनों में सीटें नहीं हैं। कई ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। अब तत्काल टिकट और स्पेशल ट्रेनों की ही उम्मीद बची है।

पटना के लिए दिल्ली से तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति जैसी प्रमुख ट्रेनों में 10 से 13 नवंबर के बीच कई श्रेणियों में रिग्रेट आ रहा है। कई में वेटिंग 100 से 400 के पार पहुंच गई है। 18 सितंबर को नई दिल्ली-राजेंद्रनगर तेजस में 10 नवंबर को थर्ड एसी में वेटिंग लिस्ट 410 पहुंच गई थी। 11 नवंबर को यह 427 और 12 नवंबर को 463 तक पहुंच गई। इन तारीखों पर फर्स्ट और सेकेंड एसी में भी कई जगह रिग्रेट की स्थिति है। नई दिल्ली-राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस (12394) में 10 नवंबर को फर्स्ट एसी में वेटिंग लिस्ट 21, सेकेंड एसी में वेटिंग लिस्ट 52, थर्ड एसी में वेटिंग लिस्ट 159 और स्लीपर में वेटिंग लिस्ट 134 के साथ सभी श्रेणियों में रिग्रेट दिख रहा है। दक्षिण भारत से बिहार आने वाले यात्रियों के लिए भी सीटों का संकट दिख रहा है। मुंबई से आने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में 210 की वेटिंग है। कुछ श्रेणियों में रिग्रेट दिख रहा है। ट्रेनों में सीट नहीं मिलने के बाद यात्री हवाई सफर की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन मुंबई से बिहार आने के लिए किराया करीब 40 हजार रुपये तक पहुंच गया है। बेंगलुरु से पटना या दरभंगा के लिए सीधी फ्लाइट उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को दूसरे शहरों के रास्ते आने की मजबूरी है। दिल्ली से पटना की फ्लाइट का किराया 26 हजार रुपये से अधिक और दरभंगा का 17 हजार रुपये से अधिक तक पहुंच गया है।

बसों में भी एडवांस बुकिंग, किराया बढ़ा

लंबी दूरी की एसी और नॉन एसी बसों में भी सीटों की बुकिंग तेजी से हो रही है। दिल्ली, पंजाब, रांची, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश समेत अन्य शहरों से बिहार आने वाली बसों में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। बस ऑपरेटरों ने किराया काफी बढ़ा दिया है। त्योहार के दौरान निजी वाहन से बिहार आने-जाने का किराया सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना तक पहुंचने की बात यात्री बता रहे हैं।

10 से 17 नवंबर के बीच ज्यादा दबाव

सबसे ज्यादा दबाव 10 से 17 नवंबर के बीच दिखाई दे रहा है। यानी दीपावली के आसपास घर आने और छठ के बाद नौकरी-पेशा वाले लोगों के वापस लौटने की अवधि में ट्रेनों की मांग बढ़ गई है। खासकर दिल्ली और दक्षिण भारत से बिहार आने वाली ट्रेनों में कई तिथियों पर सामान्य कोटे में कन्फर्म टिकट उपलब्ध नहीं है।

पूजा स्पेशल से उम्मीद

दशहरा, दीपावली और छठ में घर आने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन में आरक्षित सीटों की मारामारी शुरू हो गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, पुणे और हैदराबाद से पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत बिहार के तमाम स्टेशनों पर पहुंचने वाली ट्रेनों में सीटें नहीं हैं। कई ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। अब तत्काल टिकट और स्पेशल ट्रेनों की ही उम्मीद बची है।

चॉकलेट और 10 रुपए देकर 9 साल की बच्ची से रेप

दुष्कर्मी को 20 साल की सजा; 3 लाख मुआवजे का आदेश

सासाराम (संवाददाता)। बिहार के सासाराम में सूर्यपुरा थाना क्षेत्र में नौ वर्षीया बच्ची से दुराचार के करीब दो साल पुराने मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज-सात अरविंद की विशेष पॉक्सो अदालत ने बड़ी मोहल्ला सूर्यपुरा निवासी धर्मवीर पासवान को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अदालत ने पीड़ित बच्ची के पुनर्वास के लिए तीन लाख रुपये मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया है। इसके लिए राज्य सरकार को पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। मामले में बच्ची की मां ने सूर्यपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, नौ सितंबर 2024 की शाम करीब सात बजे बच्ची दूध देने के लिए पोखरा की ओर गई थी।

रात करीब नौ बजे घर लौटने पर उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। बच्ची ने बताया कि अभियुक्त ने उसे चौकीदार के दालान के पास सुनसान स्थान पर पकड़ लिया था। चॉकलेट और 10 रुपये देने का लालच देकर दालान के पीछे झाड़ियों में ले जाकर दुराचार किया। विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि मामले के ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही कराई गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया और 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

बिक्रमगंज शहर के एक मोहल्ला में एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने की घटना प्रकाश में आया है। घटना बीते बुधवार की रात की बताई जाती है। पीड़ित लड़की के मां के लिखित बयान पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष दिनेश मालाकार ने बताया कि इस संबंध में बीते गुरुवार के संध्या करीब सात बजे पीड़ित लड़की के मां द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। जिसमें मोहल्ले के मोहित नामक युवक को आरोपित किया गया है। घटना में पीड़ित का मेडिकल जांच कराने के बाद कारवाई शुरू कर दी गई है। घटना के बारे में बताया जाता है पीड़ित लड़की घर में छत पर बुधवार की रात सोई हुई थी। तभी मोहित नाम का एक लड़का आया और दुष्कर्म की घटना का अंजाम दे दिया।

अनंत सिंह और नीरज के झगड़े पर ललन सिंह साइलेंट

पटना (संवाददाता)। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में विधायक अनंत सिंह और एमएलसी नीरज कुमार के झगड़े से घमासान छिड़ा हुआ है। अब इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने चुप्पी साध ली है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि जेडीयू में किसी तरह का मतभेद नहीं है, पार्टी एकजुट है। एक दिन पहले पटना में हुए विधायक एवं एमएलसी के प्रबोधन कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर भी ललन सिंह ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि वह शुक्रवार को गुजरात में थे।

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शनिवार को पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, 'पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। जदयू एकजुट है। 1994 में नीतीश कुमार ने जब समता पार्टी का गठन किया था, तब से पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। आपसी सहमति और आपसी विचार विमर्श से पार्टी चलती है। आज भी यह परंपरा चल रही है। सभी नेता एकमत हैं।' ललन सिंह ने शुक्रवार को जदयू के प्रबोधन कार्यक्रम में नहीं शामिल होने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम था। उसी दिन मेरा कार्यक्रम गुजरात में था।

दरअसल, आगामी बिहार विधान परिषद के चुनाव से पहले मोकामा से जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने पार्टी के पटना स्नातक सीट से एमएलसी नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आगामी चुनाव में नीरज का विरोध करने का ऐलान किया और निर्दलीय अनुज सिंह को समर्थन दे दिया है।

सावधान!

कहीं आप पाकिस्तान में बैन फेस क्रीम तो नहीं लगा रहे, नेपाल के रास्ते बिहार आ रहा विदेशी माल

भागलपुर(संवाददाता)। पड़ोसी देश पाकिस्तान में निर्मित और प्रतिबंधित सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अब नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से पूर्वी बिहार और कोसी-सीमांचल के बाजारों में धड़ल्ले से खपाई जा रही है। इंडो-नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की टीम द्वारा भारी मात्रा में पाकिस्तानी क्रीम पकड़े जाने के बाद इस बड़े अवैध नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद भागलपुर समेत कोसी और सीमांचल के जिलों में भी ड्रग्स विभाग मुस्तैद हो गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने पाकिस्तान के लाहौर स्थित कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल, इन दोनों क्रीमों में निर्धारित मानकों से कई गुना अधिक मात्रा में खतरनाक भारी धातुएं (हेवी मेटल्स) और पारे (मर्करी) जैसे विषैले तत्व पाए गए हैं। इन अनधिकृत दोनों क्रीम के आयात का कोई वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक इनके इस्तेमाल से त्वचा खराब होने के साथ-साथ किडनी और तंत्रिका तंत्र को भी गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

पूर्वी बिहार और ग्रामीण इलाकों में इन पाकिस्तानी क्रीमों की मांग बहुत अधिक है। कम कीमत में तेजी से रंग गोरा करने और चेहरे पर चमक लाने के दावों के कारण युवा और महिलाएं आसानी से इनके झांसे में आ जाते हैं। अन्य ब्रांडेड और महंगी हर्बल क्रीमों की तुलना में ये काफी कम दाम पर मिल जाती हैं, जिससे कम बजट वाले उपभोक्ता इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं।

खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक, तस्कर नेपाल की खुली सीमाओं का फायदा उठाकर इन कॉस्मेटिक उत्पादों को बिहार के तराई वाले जिलों सीमांचल के रास्ते भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जैसे बड़े बाजारों तक पहुंचा रहे हैं। कॉस्मेटिक बाजारों के जानकारों का अनुमान है कि कोसी-सीमांचल और पूर्वी बिहार के इलाकों में इन प्रतिबंधित क्रीमों की खपत प्रतिमाह हजारों पीस तक पहुंच चुकी है। तस्करी कर इस क्रीम को सीमाई इलाकों के जिलों में पहुंचाया जा रहा है। एसएसबी द्वारा पकड़ी गई क्रीम की खेप को जांच के लिए सीडीएससीओ के पास भेज दिया गया है। ड्रग्स विभाग ने भागलपुर सहित सभी जिलों में कॉस्मेटिक दुकानों की औचक जांच शुरू कर दी है। सीमाई जिलों की स्थानीय पुलिस की टीम ने भी आमलोगों से अपील की है कि कोई दुकानदार प्रतिबंधित गोरी या चांदनी क्रीम बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को तस्करी रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

अमेरिका में लागू हुआ नया आव्रजन नियम, भारतीय ग्रीन कार्ड आवेदकों पर पड़ेगा सीधा असर

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका की सरकार ने ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास) की चाह रखने वाले विदेशी नागरिकों, विशेषकर भारतीय पेशेवरों के लिए नियमों में एक बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने साल 2022 के पब्लिक चार्ज नियमों को रद्द कर दिया है। इसकी जगह अब अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन (यूएससीआईएस) को यह तय करने का अधिकार दिया है कि कौन भविष्य में अमेरिकी सरकार पर आर्थिक रूप से बोझ बन सकता है। यह नया नियम 18 सितंबर या उसके बाद किए जाने वाले फॉर्म आई-485, स्थायी निवास पंजीकरण या स्थिति समायोजन के लिए आवेदन पर लागू होगा।

इससे पहले दाखिल किए गए और लंबित आवेदनों पर पूर्व नियम लागू होगा। फेडरल रजिस्टर में स्पष्ट किया है कि 18 सितंबर से पहले प्राप्त आय-आधारित सार्वजनिक लाभों को 2022 के नियम के अनुरूप माना जाएगा। नए आवेदनों पर ही नया नियम लागू किया जाएगा। नए ढांचे के तहत कोई निश्चित वेतन या आय की सीमा तय नहीं की गई है, जिसके नीचे आने पर आवेदन खारिज हो जाए। इसके बजाय, यूएससीआईएस के अधिकारी अब आवेदक की समग्र परिस्थितियों का आकलन करने के लिए 5 कानूनी कारकों को एक साथ मिलाकर देखेंगे।

इनमें आवेदक की उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति, पारिवारिक स्थिति, संपत्ति, संसाधन और वित्तीय स्थिति, शिक्षा का स्तर और कौशल शामिल होगा। उसके बाद ही उनके आवेदनों पर निर्णय होगा। पहले के नियमों में सरकार केवल नकद सहायता या दीर्घकालिक संस्थागत देखभाल पर ध्यान देती थी, लेकिन नए नियम में बदलाव किए गए हैं। अब किसी आवेदक के नकद सहायता, आवास सहायता, खाद्य सहायता और सरकार द्वारा वित्त पोषित कुछ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया है, तो उन्हें भी मामलों के हिसाब से जांच के दायरे में शामिल किया जा सकता है।

अधिकारी पूरे मामले की समग्रता को देखकर ही आवेदन पर अंतिम फैसला लेंगे। यह बदलाव विशेष रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवरों और अन्य कुशल कामगारों के लिए प्रासंगिक है जो अस्थायी अमेरिकी आप्रवासन स्थिति से स्थायी निवास में परिवर्तित हो रहे हैं। इनमें ईबी-1 में शामिल प्राथमिकता वाले कर्मचारी, ईबी-2 में शामिल उन्नत डिग्री वाले पेशेवर, ईबी-3 में शामिल कुशल कर्मचारी और पेशेवर, कुछ अन्य कर्मचारी, निवेशक और कुछ धार्मिक कार्यकर्ता शामिल हैं।

हालांकि, बोझ माने जाने के लिए आवेदक की ग्रीन कार्ड श्रेणी और व्यक्तिगत परिस्थितियां मायने रखेंगी। अमेरिकी नागरिकों के विदेशी जीवनसाथी, माता-पिता या बच्चों के पारिवारिक-स्पॉन्सरशिप वाले आवेदनों पर भी नया पब्लिक चार्ज टेस्ट लागू होगा। हालांकि, शरणार्थियों, एसिली, मानव तस्करी के पीड़ितों और कुछ विशेष श्रेणियों को इस पब्लिक चार्ज नियम से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

जांच के बाद यूएससीआईएस को लगेगा कि कोई आवेदक केवल पब्लिक चार्ज होने के आधार पर अयोग्य हो रहा है, तो एजेंसी खुद उसे पब्लिक चार्ज बॉन्ड (फॉर्म आई-945) भरने का आमंत्रण देगी। जहां लागू हो, यूएससीआईएस फॉर्म आई-864, समर्थन शपथ पत्र पर विचार कर सकता है। यह फॉर्म प्रायोजक से वित्तीय प्रतिबद्धता प्रदान करने के लिए है, जहां इसकी आवश्यकता होती है। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि आवेदक की परिस्थितियों के अन्य सभी पहलू अप्रासंगिक हो जाते हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, यूएससीआईएस सार्वजनिक प्रभार निर्धारण करते समय व्यापक साक्ष्यों के साथ-साथ हलफनामे पर भी विचार कर सकता है। ऐसे में थोड़ी राहत मिल सकती है। नए नियम के तहत ग्रीन कार्ड के भारतीय आवेदकों की वित्तीय और व्यक्तिगत स्थिति की जांच अब अधिक व्यापक होगी। स्थिर वित्तीय स्थिति वाले पेशेवरों के लिए आकलन योग्यता के आधार पर होगा, जबकि जटिल मामलों में जांच का दायरा बढ़ गया है। इस नीति के खिलाफ कानूनी चुनौतियां भी सामने आई हैं, लेकिन वर्तमान में यह नियम प्रभावी है। विस्तृत जानकारी के लिए आप संबंधित आधिकारिक स्रोतों का अवलोकन कर सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में बेटे से मिलने पहुंचीं भारतीय महिला और उनकी बहू की सड़क हादसे में मौत

मेलबर्न (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में अपने बेटे से मिलने पहुंचीं आंध्र प्रदेश की 67 वर्षीय रमा देवी की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी कार एक पोर्श कार से टकरा गई थी। घटना के समय रमा देवी के साथ उनकी 33 वर्षीय बहू नेहा बोम्माली भी थीं, जिनकी मौत हुई है। नेहा के परिवार में उनके पति और 2 बच्चे हैं, जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है। रमा देवी 2 महीने पहले अपने बेटे से मिलने मेलबर्न गई थीं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसा पॉइंट कुक के पामर्स रोड पर हुई, तब रमा देवी और नेहा जीटी प्रसाद के साथ टोयोटा कार में यात्रा कर रही थीं। खबरों के मुताबिक दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रसाद दुर्घटना में बच गए। आसपास के लोग उनकी मदद को दौड़े, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। पोर्श कार के चालक की पहचान प्वाइंट कुक निवासी 53 वर्षीय व्यक्ति के रूप में हुई है। वह पुलिस हिरासत में है। विशाखापट्टनम की रहने वाली रमा देवी के पति जीटी प्रसाद, विशाखापट्टनम जिला क्रिकेट संघ के पूर्व संयुक्त सचिव और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी हैं। रमा 2 महीने पहले अपने परिवार से मिलने, अपने पोते-पोतियों के साथ समय बिताने और एक पारिवारिक समारोह में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थीं। नेहा के पति वरुण चंद्र गुना नेहा और रमा देवी को भारत वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं।

दिल्ली में किशोरी से गैंगरेप के बाद चाकू से गोदकर हत्या, प्रेमी ने दोस्तों संग की दरिंदगी; खुले मैदान में मिला नोंचा हुआ शव

नई दिल्ली (एजेंसी)।

बाहरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के बाद बर्बरता से हत्या करने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरिंदगी की इस वारदात को किशोरी के कथित प्रेमी ने अपने तीन नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया था।

पुलिस की शिकायत के डर से आरोपियों ने किशोरी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी जान ले ली। दिल्ली पुलिस ने 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद एक संदिग्ध टेंपो के जरिए इस खौफनाक वारदात की गुत्थी सुलझाते हुए मुख्य आरोपी और तीन नाबालिगों को दबोच लिया है।

वारदात का खुलासा 13 सितंबर की सुबह तब हुआ, जब स्वरूप नगर थाना पुलिस को कुशक रोड स्थित लाल बाउंड्री के पास जयपाल राणा के खेत के खुले मैदान में एक शव पड़े होने की सूचना मिली। शव बेहद क्षत-विक्षत हालत में था और जंगली जानवरों ने उसे बुरी तरह नोंच खाया था। चेहरे और शरीर की हालत देखकर शुरुआत में पुलिस ने उसे किसी वयस्क महिला का शव समझा था। क्राइम और फोरेंसिक टीमों ने मौके से साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बाद में जब परिजनों ने पहचान की, तब यह खुलासा हुआ कि मृतका महज एक नाबालिग किशोरी थी।

50 कैमरों की फुटेज और एक संदिग्ध टेंपो से खुला राज

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लोकेश वरन के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने घटनास्थल और आसपास के सभी रास्तों की पड़ताल शुरू की। अंधेरा होने के बावजूद 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करने पर एक संदिग्ध टेंपो की हलचल नजर आई। नंबर प्लेट साफ न दिखने पर पुलिस ने अलग-अलग चौराहों के कैमरों को जोड़कर टेंपो का पूरा रूट ट्रैक किया। आखिरकार 15 सितंबर की रात यह टेंपो खड्डा कॉलोनी में खड़ा मिल गया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद पूरे हत्याकांड की परतें खुलती चली गईं।

शराब पार्टी के बाद हैवानियत, फिर भेद खुलने के डर से कत्ल

पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी मृतका का कथित प्रेमी था। वारदात वाली रात उसने अपने दोस्तों के साथ पहले जमकर शराब पी। इसके बाद चारों ने मिलकर सुनसान इलाके में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। हैवानियत के बाद आरोपियों को डर सताने लगा कि किशोरी घर जाकर परिजनों या पुलिस से इसकी शिकायत कर देगी। इसी खौफ में उन्होंने चाकू निकालकर किशोरी पर ताबड़तोड़ वार किए और उसे तड़प-तड़प कर मरने के लिए खुले मैदान में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल दो चाकू, घटना के समय पहने गए खून से सने कपड़े और टेंपो को जब्त कर लिया है।

बाबा फरीद आगमन पर्व से पहले आतंकी साजिश नाकाम

फरीदकोट (एजेंसी)। बाबा फरीद आगमन पर्व से पहले फरीदकोट में काउंटर इंटेलिजेंस ने कथित आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए दो ग्रेनेड के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गुरु अर्जन देव नगर निवासी नवजोत सिंह उर्फ नव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, नवजोत कनाडा का पीआर है और करीब एक सप्ताह पहले ही भारत लौटा था। काउंटर इंटेलिजेंस के मुताबिक, आरोपी के पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से संपर्क होने का संदेह है। आरोप है कि उसने ड्रोन के जरिए विस्फोटक सामग्री मंगवाई थी। टीम ने उसे फिरोजपुर से एक्टिवा पर फरीदकोट आते समय गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, फाजिल्का में एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। पांच दिवसीय बाबा फरीद आगमन पर्व से पहले हुई इस गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आरोपी से उसके नेटवर्क और संभावित निशाने के संबंध में पूछताछ करेगी।

पंजाब के बटाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमला, फेंके गए अंडे-टमाटर

बटाला (एजेंसी)। पंजाब के बटाला में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमला हुआ है। कुछ लोगों ने उनके काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके। इस हमले के बाद बिट्टू ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और तीन हमलावरों को पकड़ने का दावा किया है। रवनीत सिंह बिट्टू पर बटाला के घासीतपुर गांव के पास हमला हुआ है। वह ड्रग्स के खिलाफ भाजपा की यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी बीच उनके काफिले पर हमला हुआ। कई लोगों ने अंडे और टमाटर फेंके। साथ ही, लोगों को नारेबाजी करते हुए देखा गया। बिट्टू ने दावा किया कि इस हमले में उनकी गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। घटनास्थल पर ही रवनीत बिट्टू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, आज हमें ड्रग्स के खिलाफ एक यात्रा निकालनी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार और ड्रग एडिक्ट्स सब मिले हुए हैं। वे पिछले साढ़े चार साल से यही कर रहे हैं। वहां करीब 500 लोग थे। मैं अपनी गाड़ी से उनके बीच से गुजरा। मेरे पास जेड-प्लस सिक्योरिटी है और मेरे साथ करीब 100 सुरक्षाकर्मी होते हैं। सुरक्षा के लिए स्थानीय डीएसपी और एसपी भी पुलिस के साथ वहां मौजूद थे।

उन्होंने तीन लोगों को पकड़ने का दावा करते हुए कहा कि इन लोगों को फोन जब्त कर लिए गए हैं। उनके फोन चालू हैं, जिन पर लगातार कहा जा रहा था कि उन्हें घेरो, उन्हें मारो, उनकी जान ले लो। उन्होंने गाड़ियों पर हमला किया और गाड़ियों की खिड़कियां तोड़ दीं। अंडे और टमाटर तो छोटी बात है। उनमें से कुछ के पास हथियार भी थे।

बिट्टू ने कहा, जब हमला किया गया तो सुरक्षाकर्मियों ने दो लोगों को पकड़ा। बाकी अन्य लोग वहां से भाग गए थे। ये लोग दोबारा हमला करने आए थे। इस समय कुछ लोग फिर पकड़े गए। ये लोग प्लानिंग के तहत हमला करने आए थे। इन लोगों को फोन हमारे पास हैं। इनके फोन सारे राज खोलेंगे। हम जांच के लिए फोन भेजेंगे। आरोपियों के बारे में उन्होंने कहा, इनका कोई कसूर नहीं है। ये लोग अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसी बीच, रवनीत बिट्टू ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, हम लोग यहां सुबह करीब 9 बजे से बैठे हैं, लेकिन पौने 11 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

आईफोन की भीड़ देख सोनू सूद ने कसा तंज, कहा- असली अपग्रेड फोन का नहीं समाज का करो

मुंबई (एजेंसी)। भारत में दिखावे के चक्कर ज्यादा खर्च करने का चलन नया नहीं है। कल भी एक नजारा दिखा, जब आईफोन 18 प्रो सीरीज के फोन खरीदने के लिए सुबह से ही एप्पल स्टोर के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसे देखते हुए अभिनेता सोनू सूद ने लोगों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि महंगे फोन से झूठी शान दिखाने और कर्जदार बनने से बेहतर है कि लोग अपनी गाढ़ी कमाई और ऊर्जा को समाज की भलाई में लगाएं।

अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें एप्पल स्टोर के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ दिख रही है। अभिनेता ने अपनी इस पोस्ट के जरिए लोगों को केवल स्मार्टफोन के दिखावे और कर्ज के जाल में फंसने के बजाय सामाजिक सुधार और दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करने की सीख दी है। उन्होंने लिखा, नया फोन, नई ईएमआई, वही पुराने बिल! शायद यह समय सिर्फ अपने फोन को अपग्रेड करने का नहीं, बल्कि समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कतार (लाइनों) में खड़े होने का है। असली अपग्रेड एक बेहतर समाज का निर्माण है।

बता दें कि एप्पल के नए आईफोन 18 प्रो सीरीज की बिक्री शुक्रवार सुबह 8 बजे से भारत में शुरू हो गई है। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों में एप्पल स्टोर और आधिकारिक दुकानों के बाहर लोग सुबह से लंबी कतारों में खड़े नजर आए।

भारत में इसके बेस मॉडल की कीमत 1,64,900 रुपए से शुरू है। आईफोन 18 प्रो को लेकर पूरे देश में खुमार इस कदर है कि कई लोगों ने पहले से ही ऑनलाइन प्री-बुकिंग करा रखी थी।

बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र, पूर्वी और मध्य भारत में बढ़ सकती है बारिश

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने के साथ ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी और मध्य भारत में बारिश का दौर जारी रख सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार आज से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। वहीं, देश के कई अन्य हिस्सों में अभी बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारों का दौर जारी है।

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाला नया मौसमी तंत्र पूर्वी और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। इस तंत्र की शुरुआत उत्तरी थाईलैंड के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण से होने का अनुमान है। इसके उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर पहुंचने तथा कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बाद अगले तीन से चार दिनों में यह तंत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट की ओर जा सकता है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा यह तंत्र धीरे-धीरे मजबूत हो सकता है। स्काईमेट के मौसम विशेषज्ञ महेश पलावत ने भी इसके पूर्वी तट की ओर बढ़ने के साथ सक्रिय होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह का मौसमी चक्र सामान्य तौर पर जून-जुलाई में देखने को मिलता है, लेकिन इस वर्ष सितंबर में भी ऐसा चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है।

अनुमानों के मुताबिक, मानसून की वापसी शुरू होने के बाद भी बारिश का दौर पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। नया मौसमी तंत्र ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बाद में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ा सकता है। इसके अलावा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की संभावना बन सकती है। तंत्र के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने के साथ पूर्वी तट के कई इलाकों में मौसम प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की द्रोणिका के मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में सक्रिय रहने की संभावना है। इसका असर यह होगा कि जहां उत्तर-पश्चिम भारत धीरे-धीरे शुष्क मौसम की ओर बढ़ेगा, वहीं मध्य और पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश जारी रह सकती है। राजस्थान में शुष्क मौसम की शुरुआत के संकेत मिलने लगे हैं। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अपेक्षाकृत शुष्क परिस्थितियां बन सकती हैं, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिमी भारत में गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में भी धीरे-धीरे शुष्क मौसम बढ़ने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और रत्नागिरी सहित कई हिस्सों में मौजूदा बारिश के बाद गतिविधियों में कमी आ सकती है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून की वापसी के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम में असमान बदलाव सामान्य प्रक्रिया है। मानसून पूरे देश से एक साथ वापस नहीं लौटता। मौसम विभाग किसी क्षेत्र से मानसून की वापसी की घोषणा करने से पहले लगातार बारिश बंद होने, प्रतिचक्रवात बनने और वातावरण में नमी की मात्रा में उल्लेखनीय कमी जैसे संकेतों का आकलन करता है।

उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून की वापसी का असर केवल बारिश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि तापमान में भी बदलाव आने लगता है। बादल कम होने और आसमान साफ होने पर दिन के समय सूर्य की गर्मी जमीन को अधिक गर्म कर सकती है। वहीं, रात में बादलों की कमी के कारण धरती की गर्मी तेजी से बाहर निकलती है, जिससे रात के तापमान में गिरावट आ सकती है।

इससे दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ सकता है। ऐसे में दोपहर के समय गर्मी महसूस होने के बावजूद सुबह और शाम का मौसम अपेक्षाकृत ठंडा लग सकता है। मौसम में अचानक होने वाले इन बदलावों का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, तापमान में उतार-चढ़ाव से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, विशेषकर गर्मी या मौसम संबंधी तनाव की स्थिति में। आने वाले दिनों में देश के मौसम का स्वरूप दो अलग-अलग तस्वीरें पेश कर सकता है। उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून की वापसी के साथ शुष्क परिस्थितियां बढ़ेंगी, जबकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियों को सक्रिय रख सकता है। दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में भी इस मौसमी तंत्र के प्रभाव से बारिश बढ़ने की संभावना है।

बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष हत्याकांड

सीबीआई जांच में हो रही थी देरी, दो साल से जेल में बंद 5 आरोपियों को मिली जमानत

चेन्नई (एजेंसी)। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की सनसनीखेज हत्या के मामले में चेन्नई की प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने इस मामले में जेल में बंद पांच आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है.

इस याचिका पर चेन्नई प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट के जज कार्तिकेयन के समक्ष सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है. जांच पूरी होने के बाद अदालत में कानूनी मुकदमा कब शुरू होगा, इसकी कोई समय-सीमा तय नहीं है. ऐसे में आरोपियों को अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता. दलीलों को सुनने के बाद जज ने सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले का हवाला दिया. जज ने पॉइंट आउट किया कि देश की सर्वोच्च अदालत के मुताबिक यदि त्वरित सुनवाई न होने के कारण आरोपियों के मौलिक अधिकारों पर असर पड़ता है, तो केवल अपराध की गंभीरता या उसकी प्रकृति के आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता. इसी संवैधानिक अधिकार के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली.

यूपीआई पर मायावती ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा-सरकार कुछ भी कहे, जेब तो जनता की ही कटेगी

लखनऊ (एजेंसी)। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने यूपीआई को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए फैसले पर आपत्ति जाहिर की है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यूपीआई डिजिटल लेनदेन को पहले खूब बढ़ावा दिया. अब उस लेनदेन पर शुल्क वसूलने की नई व्यवस्था कर डाली है, जो लोगों की नजर में प्रथम दृष्टया मुनाफाखोरी के पूंजीवादी रवैये के तहत जनता से दोनों हाथों से टैक्स वसूली है, इससे जनता में बेचैनी और आक्रोश स्वाभाविक है.

मायावती ने कहा कि वैसे तो जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने की इस व्यवस्था को कर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन 15 अक्तूबर से लागू होने वाली इस व्यवस्था को चाहे जो भी नाम दिया जाए, जेब तो अन्ततः आम जनता की ही कटेगी. उसका ही खर्च बढ़ेगा. बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यह भी सभी को पता है कि देश की बहुसंख्यक जनता गरीबी व जबरदस्त महंगाई की मार से त्रस्त है. उनके बच्चे अशिक्षा, बेरोजगारी व अव्यवस्था से पीड़ित हैं, ऐसे में सरकार की नीति व कार्ययोजना लाभ कमाने वाली व्यावसायिक कम व कल्याणकारी ज्यादा हो तो यह उचित

होगा. जनता की तंगी, दुख-तकलीफ की अगर सरकार चिन्ता नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा?

बसपा मुखिया ने कहा कि यूपी सरकार ने करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के 14,500 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने की घोषणा की है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को कथित स्मार्ट पढ़ाई से पहले उन्हें बुनियादी शिक्षा की ज़रूरतें यानी स्कूली बच्चों के सर पर छत, उनके लिये बेंच, कुर्सी, किताब, शौचालय, मैदान, साफ-सफाई आदि की सही व्यवस्था पूरी की जाएं. यह सब प्रति स्कूल करीब दो लाख रुपये में क्या संभव हो पायेगा? इस पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक जरूर विचार करे.

बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बहुचर्चित सामाजिक न्याय की ज़रूरत व मांग यही है कि यूपी सरकार न्यायालय में अगर इस बात की पुरज़ोर पैरवी करती कि एससी समाज के हित व कल्याण के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के धन से सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, कन्नौज व जालौन में बनाए गए मेडिकल कॉलेजों में एससी वर्ग के लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था 50 प्रतिशत के सामान्य आरक्षण से अलग है. इस व्यवस्था से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की भरपूर उपयोगिता साबित होती है तो शायद कोर्ट इस पर जरूर सकारात्मक विचार करता और इस पर रोक नहीं लगाता, लेकिन अब जबकि हाईकोर्ट ने इस पर पाबन्दी लगा दी है और मेडिकल दाखिला भी अब यहां इससे प्रभावित है, ऐसे में यूपी सरकार तत्काल सुप्रीम कोर्ट में आपेक्षित राहत के लिए अपील करे.

'वह मेरे जीवन का एक बहुत बुरा अनुभव था', स्मिथ ने द. अफ्रीका दौरे से पहले सैंडपेपरगेट को किया याद

नई दिल्ली (एजेंसी)। स्टीव स्मिथ ने कहा कि 2018 के बॉल-टैम्परिंग स्कैंडल की यादें उन्हें कभी-कभी अब भी आती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस बल्लेबाज को इस बात की चिंता नहीं है कि उस बदनाम घटना के बाद पहली बार टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका लौटने पर उन्हें लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। स्मिथ उस विवाद के मुख्य लोगों में से एक थे जो मार्च 2018 में केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के दौरान हुआ था। सैंडपेपर का इस्तेमाल करके गेंद की हालत बदलने की योजना में अपनी भूमिका स्वीकार करने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया, 12 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया और ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी से हटा दिया गया।

डेविड वॉर्नर पर भी एक साल का बैन लगाया गया और उनसे कप्तानी की जिम्मेदारियां छीन ली गईं, जबकि कैमरन बैनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। लगभग आठ साल बाद स्मिथ 9 अक्टूबर से डरबन में शुरू होने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ दक्षिण अफ्रीका लौटने की तैयारी कर रहे हैं। 37 वर्षीय खिलाड़ी ने माना कि उनके सस्पेंशन से जुड़ी घटनाओं को पूरी तरह से भूलना मुश्किल है, खासकर दक्षिण अफ्रीका छोड़ने के बाद मीडिया के भारी ध्यान का सामना करने की यादें।

स्मिथ ने प्रकाशित एक इंटरव्यू में न्यूज कॉर्प को बताया, 'मुझे कैमरे ज्यादा पसंद नहीं हैं... सच कहूं तो कैमरे के सामने मुझे घबराहट होती है। वह मेरे जीवन का एक बहुत बुरा अनुभव था और जब मैं कैमरे की फ्लैश की आवाज सुनता हूं, तो मुझे एक तरह से वह सब फिर से याद आ जाता है।' उन्होंने आगे कहा, 'जेम्स सदरलैंड का यह बताना कि मुझे एक साल के लिए बैन किया जा रहा है - वे 24-48 घंटे। वह समय और जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट से गुजरते समय लोगों की भीड़ से घिर जाना और फिर वापस उड़ान भरना और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। मुझे अब भी कभी-कभी उसकी हल्की-फुल्की यादें आती हैं।'

स्मिथ ने कहा कि स्कैंडल के बाद के शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे और इस अनुभव ने उन्हें जरूरी सबक सिखाए। उन्होंने कहा, 'यह निश्चित रूप से एक मुश्किल दौर था, खासकर उसके कुछ दिन बाद का शुरुआती समय। मेरी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं ऐसी स्थिति में दोबारा नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन मैंने निश्चित रूप से उससे सीखा है और अपने जीवन में आगे बढ़ पाया हूं।' यह सीरीज 2018 के बाद ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण अफ्रीका में पहला टेस्ट दौरा होगा और यह पिछले साल लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दोनों टीमों के आमने-सामने होने के बाद हो रही है।

दक्षिण अफ्रीका को लगा झटका

तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर

केप टाउन (एजेंसी)। चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम से बाहर हो गए है। टीम में उनकी जगह नाकोबानी मोकोएना को बुलाया गया है। पिछले सप्ताह टाइटन्स और डॉल्फ़िन्स के बीच घरेलू प्रथम श्रेणी सीजन के पहले मैच में एनगिडी की दाहिनी हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी।

स्कैन से पुष्टि हुई कि उन्हें ठीक होने के लिए कुछ समय लगेगा। कगिसो रबाडा और ओटनिल बाटमैन के बाद एनगिडी तीसरे तेज गेंदबाज हैं जो इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। पिछले सप्ताह एनगिडी ने डॉल्फ़िन्स की पहली पारी में आठ ओवर और दूसरी पारी में 8.3 ओवर फेंके। यह उनके साथी तेज़ गेंदबाजों माकर जानसन और बेयर्स स्वानपओल की तुलना में कम था, जिन्होंने क्रमश: 26 और 20.3 ओवर फेंके थे।

एनगिडी कुछ समय के लिए मैदान से बाहर भी रहे, लेकिन वापस लौटे और मैच के अंत में मौजूद थे। तब तक डॉल्फ़िन्स के लिए खेल रहे बाटमैन भी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण बल्लेबाज़ी करने में असमर्थ हो गए थे। एनगिडी की जगह 20 साल के तेज गेंदबाज नाकोबानी मोकोएना को वनडे टीम में शामिल किया गया है। मोकोएना को दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया दौरे के दौरान अपनी पहली वनडे कैप मिली थी।

मोकोएना वेस्टर्न प्रोविंस के खिलाफ फर्स्ट-क्लास मुकाबले में डॉल्फ़िन्स के लिए खेल रहे थे और उन्होंने पहले दिन 19 ओवर फेंके, जिसमें 78 रन देकर 1 विकेट लिया। उन्हें वनडे की तैयारी के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम में शामिल होने के लिए उस मैच से हटा दिया गया है और उनकी जगह बयांडा माजोला को टीम में लिया गया है। वनडे में तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान जानसन संभालेंगे, जिनके जुड़वां भाई डुआन भी टीम में हैं। अन्य तेज गेंदबाजी विकल्पों में कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएत्जी और क्वेना मापाका शामिल हैं।

WWE स्टार की पहचान का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी, 64 वर्षीय व्यक्ति के साथ हुआ 40 लाख से ज्यादा का स्कैम

पेंसिल्वेनिया (एजेंसी)। स्टेट पुलिस के अनुसार पेंसिल्वेनिया के एक 64 वर्षीय व्यक्ति के साथ 42,700 की धोखाधड़ी हो गई। स्कैमर ने कथित तौर पर WWE स्टार रिया रिप्ले की पहचान का इस्तेमाल करते हुए इस घटना को अंजाम दिया। यह धोखाधड़ी मार्च में हुई थी और किटानिंग में पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस ने बाद में इस मामले की जानकारी जारी की।

जांचकर्ताओं ने यह नहीं बताया है कि उस व्यक्ति ने कैसे उस आदमी को पैसे देने के लिए मनाया या नकली पहचान का इस्तेमाल कैसे किया गया। पुलिस के एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने कहा कि पीड़ित ने जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि रिप्ले खुद इस घोटाले में शामिल नहीं थीं और उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी पहचान का इस्तेमाल किया जा रहा है।

पुलिस ने यह नहीं बताया है कि स्कैमर ने असल में यह धोखाधड़ी कैसे की। यह नहीं बताया गया है कि उस व्यक्ति ने क्या कहा, उन्होंने खुद को रिप्ले के तौर पर कैसे पेश किया, या किस बात ने पीड़ित को पैसे भेजने या देने के लिए मनाया। इस मामले के संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। रिया रिप्ले का पेंसिल्वेनिया घोटाले से कोई संबंध नहीं था और उनकी पहचान का इस्तेमाल उनकी जानकारी के बिना किया गया था। WWE स्टार इस घटना में शामिल नहीं थीं। खबरों के अनुसार, धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति ने रिप्ले की जानकारी के बिना उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल किया।

2024 का WWE से जुड़ा धोखाधड़ी का एक और मामला है जिसमें बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ था। 79 साल के अल्फ्रेड मैनसिनेली ने कई ऑनलाइन स्कैम में अपनी लगभग 1 मिलियन डॉलर की बचत गंवा दी। इनमें से एक स्कैम में किसी ने WWE स्टार एलेक्सा ब्लिस बनकर उनसे बात की थी। मैनसिनेली को लगा कि उनका ब्लिस के साथ रिश्ता है। उन्होंने इसके लिए अपनी रिटायरमेंट की बचत और अपनी पोती के कॉलेज फंड, दोनों का पैसा इस्तेमाल किया। यह मामला पेंसिल्वेनिया की जांच से अलग है, लेकिन दोनों मामलों में एक साफ समानता थी, किसी ने WWE रेसलर की पहचान का इस्तेमाल किया जबकि असल रेसलर उस बातचीत में शामिल नहीं था।

भारत का वस्तु निर्यात अगस्त में 26 प्रतिशत बढ़ा, व्यापार घाटे में आई कमी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत का वस्तु निर्यात अगस्त में सालाना आधार पर 26.1 प्रतिशत बढ़कर 43.81 अरब डॉलर हो गया है। यह निर्यात में देश का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि देश का निर्यात क्षेत्र लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। यह जानकारी सरकार की ओर से दी गई।

इस दौरान देश के व्यापार घाटे में भी कमी देखने को मिली है, जो कि अगस्त में 26.86 अरब डॉलर पर रहा है, जो कि एक साल पहले समान अवधि में 27.22 अरब डॉलर पर था। इस साल जुलाई में व्यापार घाटा 32 अरब डॉलर था। अगस्त में वस्तु आयात सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 72.67 अरब डॉलर पर रहा है, जो कि इस साल जुलाई में 76.22 अरब डॉलर था। मासिक आधार पर अगस्त में निर्यात में भी कमी दर्ज की गई है, जो कि जुलाई में 44.24 अरब डॉलर पर था। वाणिज्य मंत्रालय में सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा, निर्यात में बढ़ोतरी इंजीनियरिंग के सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, केमिकल और टेक्सटाइल की वजह से हुई और इनकी सबसे ज्यादा मांग अमेरिका, ईयू और ब्रिक्स देशों से थी। आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अगस्त में सोने का आयात गिरकर 2.3 अरब डॉलर रह गया, जो अगस्त 2025 के 5.4 अरब डॉलर के आंकड़े से आधे से भी कम था।

भारत की दक्षिण कोरिया से भिड़ंत, 'फाइनल 8' में जगह बनाने का बड़ा मौका

बोलोग्ना (एजेंसी)।

भारत सियोल के ओलंपिक टेनिस सेंटर में डेविस कप 2026 क्वालिफायर के दूसरे राउंड में दक्षिण कोरिया का सामना करेगा। इस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम नवंबर में इटली के बोलोग्ना में होने वाले डेविस कप 'फाइनल 8' में जगह बनाएगी।

डेविस कप रैंकिंग में 19वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम का सामना 16वें नंबर की दक्षिण कोरियाई टीम से होगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला सियोल के हार्ड कोर्ट पर खेला जाएगा। भारत के पास पहली बार मौजूदा फॉर्मेट के तहत 'फाइनल 8' में पहुंचने का मौका है।

दुनिया के 367वें नंबर के खिलाड़ी दक्षिणेश्वर सुरेश पहले एकल मुकाबले में दक्षिण कोरिया

शुरुआत युगल मैच से होगी। इसमें भारत के एन श्रीराम बालाजी और निकी कल्यांडा पूनाचा को टीम में शामिल किया गया है। अगर मुकाबला निर्णायक स्थिति तक पहुंचता है, तो सुमित नागल पहले रिवर्स एकल मैच में क्वोन सून-वू के खिलाफ खेलेंगे। इसके बाद पांचवें और आखिरी मैच में दक्षिणेश्वर सुरेश का सामना चुंग ह्योन से होगा।

भारत ने फरवरी में बेंगलुरु में नीदरलैंड्स को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वालिफायर के दूसरे राउंड में जगह बनाई थी। उस जीत में दक्षिणेश्वर सुरेश ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत की तीनों जीत में योगदान दिया था, जिसमें निर्णायक पांचवें मैच की जीत भी शामिल थी। वहीं, दक्षिण कोरिया ने पहले राउंड में बुसान में अर्जेंटीना को 3-2 से हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच डेविस कप के पिछले दो मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। इनमें 2016 में चंडीगढ़ में मिली 4-1 की जीत भी शामिल है। हालांकि, दोनों टीमों के कुल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में दक्षिण कोरिया 6-5 से आगे है।

'फाइनल 8' में जगह बनाने का इंतजार

भारत डेविस कप में तीन बार—1966, 1974 और 1987 में—रनर-अप रह चुका है। हालांकि, मौजूदा फॉर्मेट के तहत भारतीय टीम अब तक 'फाइनल 8' में जगह नहीं बना सकी है। दक्षिण कोरिया के खिलाफ जीत भारत को इस उपलब्धि के करीब ले जाएगी।

जोस बटलर ने रचा इतिहास, टी20 में 15000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने

कार्डिफ (एजेंसी)।

इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में 15,000 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड को पीछे छोड़कर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

उन्होंने गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड के दूसरे टी20 मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। बटलर ने 528 मैचों में 35.46 की औसत और 147.46 की स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए हैं। बटलर ने कई टीमों और प्रतियोगिताओं में खेलते हुए ये टी20 रन बनाए हैं।

भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर ने जुटाया 1.4 अरब डॉलर का फंड : रिपोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर ने अब तक कुल 1.4 अरब डॉलर का फंड जुटाया है, जिसमें से आधी से ज्यादा कैपिटल 2025 के बाद जुटाई गई है। यह जानकारी मंगलवार को जारी रिपोर्ट में दी गई। ट्रैकक्सन टेक्नोलॉजीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में 3,557 कंपनियां शामिल हैं, जिनमें से 281 ने फंडिंग जुटाई है और 142 ने इक्विटी निवेश हासिल किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में फंडिंग की गतिविधियों में तेजी आई है, जिसमें बड़ी राशि वाले सौदों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। फंडिंग के दो सबसे बड़े राउंड सितंबर 2025 में आईएल जेआईएन इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा जुटाया गया 198 मिलियन डॉलर का प्राइवेट इक्विटी फंड और उसी महीने में टेसॉल्व सेमीकंडक्टर का 150 मिलियन डॉलर का प्राइवेट इक्विटी राउंड था।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (ईएमएस) सबसे ज्यादा फंडिंग वाला बिजनेस सेगमेंट बनकर उभरा है। इसने 2025 से अब तक 313 मिलियन डॉलर जुटाए हैं, जिसमें पिछले 12 महीनों में जुटाए गए 89 मिलियन डॉलर भी शामिल हैं। इसके बाद एम्बेडेड हार्डवेयर का नंबर आता है, जिसने 2025 से अब तक 51.9 मिलियन डॉलर जुटाए हैं, यह पूरी रकम पिछले 12 महीनों में ही हासिल की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों का ध्यान खींचने वाले अन्य प्रमुख क्षेत्रों में पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट और फैबलैस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं। सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए बेंगलुरु मुख्य केंद्र बना रहा, जहां 626 कंपनियां हैं, जो कुल इकोसिस्टम का लगभग 18 प्रतिशत है। इस शहर की हिस्सेदारी इस सेक्टर द्वारा अब तक जुटाई गई कुल इक्विटी फंडिंग में लगभग 40 प्रतिशत रही है। नोएडा, गुरुग्राम, कोच्चि और हैदराबाद भी प्रमुख सेमीकंडक्टर क्लस्टर में शामिल रहे।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2026 में अब तक इस सेक्टर में 62 अधिग्रहण और 42 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, यह डेटा भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है, क्योंकि देश चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

इसके अलावा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन 2014-15 में लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि इसी दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात लगभग 38,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 4.24 लाख करोड़ रुपए हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक, इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 6.27 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि मोबाइल फोन का निर्यात लगभग 1,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 2.59 लाख करोड़ रुपए हो गया।

एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी

पाक ने भारत आने से किया इनकार, हॉकी इंडिया ने कहा- पाकिस्तान नहीं आया तो कोई और खेलेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। मोहाली और जालंधर में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए पहले पाकिस्तान ने टीम भेजने की मंजूरी दी थी। लेकिन अब सुरक्षा का हवाला देकर न्यूट्रल वेन्यू पर गेम्स कराने का अनुरोध किया है।

पाकिस्तान हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मोहिनउद्दीन अहमद वानी ने कहा कि इस मांग का उद्देश्य खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना है। भारत के साथ पाकिस्तान, चीन, जापान, मलेशिया और कोरिया को इसमें खेलना है। हालांकि हमारे पास पाकिस्तान ने अब तक लिखित डिमांड नहीं भेजी है।

इस पर अब हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल और एएचएफ के वाइस प्रेसिडेंट भोला नाथ सिंह का बयान आया है। उन्होंने समाचार पत्र भास्कर को बताया, 'पाकिस्तान को टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है तो भारत आना होगा, नहीं आना तो वे हट सकते हैं। पहले भी पाकिस्तान की टीम हॉकी प्रतियोगिताओं से हट चुकी है। हमारा स्टैंड क्लियर है। मुकाबले पंजाब में ही होंगे।' उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर पाकिस्तान अपनी टीम भारत नहीं भेजता तो ऐसे में बांग्लादेश या ओमान को शामिल किया जा सकता है। एशियन हॉकी फेडरेशन पुरुष की रैंकिंग में भारत 2011.03 अंकों के साथ पहले पायदान पर है और उन्हें ही मुकाबले होस्ट करने हैं। पाकिस्तान 910.0 अंक के साथ 5वें स्थान पर रहते हुए क्वालिफाई हुआ था। वो इसमें नहीं आता है तो ओमान को एंट्री मिल सकती है क्योंकि वे रैंकिंग में 595.0 अंक के साथ 7वें स्थान पर है।

ऋषभ पंत को मिली कप्तानी, सरफराज खान होंगे उपकप्तान; देखें पूरी टीम

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऋषभ पंत को आगामी वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है। इसके बाद उन्हें ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की अगुवाई की जिम्मेदारी दी गई है। पंत ने भारत के लिए आखिरी वनडे मुकाबला अगस्त 2024 में खेला था। पंत की गैरमौजूदगी में ध्रुव जुरेल को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है, जबकि केएल राहुल को वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

तेज गेंदबाज आकाश दीप भी लंबे समय बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। वह लोअर-बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण लंबे समय से मैदान से बाहर हैं। हालांकि, टीम में उनकी मौजूदगी अंतिम फिटनेस टेस्ट पास करने पर निर्भर करेगी। आकाश दीप का पिछला प्रतिस्पर्धी मुकाबला फरवरी 2026 में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच था। ऐसे में ईरानी कप में भी उनका सामना उसी टीम से हो सकता है। रेस्ट ऑफ इंडिया की तेज गेंदबाजी इकाई में मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी और आर्यन पांडे को शामिल किया गया है। वहीं, स्पिन विभाग की अगुवाई अनुकूल रॉय करेंगे। उनके साथ मानव सुथार और सारांश जैन भी टीम का हिस्सा हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली थी।

एनएचएआई की 1033 हेल्पलाइन होगी हाईटेक, एआई और रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग से मिलेगी त्वरित मदद

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कहा कि वह यात्रियों को तेज और बेहतर सहायता उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा 1033 राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन को अत्याधुनिक तकनीकों से अपग्रेड करने की योजना बना रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, अपग्रेड की गई 1033 हेल्पलाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और स्मार्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

एनएचएआई ने एक बयान में कहा कि इन सुधारों से 1033 हेल्पलाइन कॉल करने वाले व्यक्ति की सटीक लोकेशन पहचान सकेगी, भारतीय भाषाओं में की गई कॉल को समझ सकेगी और जरूरत के अनुसार सहायता को अधिक तेजी से मौके तक भेज सकेगी।

हालांकि, आपातकालीन परिस्थितियों में जहां मानवीय निर्णय और समझ जरूरी होती है, वहां मानव ऑपरेटरों की भूमिका पहले की तरह महत्वपूर्ण बनी रहेगी। एनएचएआई द्वारा प्रोत्साहित कंपनी इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) ने अगली पीढ़ी की 1033 हेल्पलाइन और कॉल सेंटर के विकास, डिजाइन, संचालन और रखरखाव के लिए कंपनियों और समूहों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) आमंत्रित किया है। आईएचएमसीएल इस नई प्रणाली को विकसित करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों से सुझाव और तकनीकी राय भी प्राप्त करेगा, ताकि एक भरोसेमंद, विस्तार योग्य और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप प्रणाली तैयार की जा सके। इसके लिए उद्योग जगत की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

अपग्रेड की गई 1033 हेल्पलाइन से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सहायता सेवाएं अधिक तेज, बेहतर समन्वित और यात्रियों के लिए सुविधाजनक होने की उम्मीद है। तकनीक और मानवीय सहयोग के बेहतर तालमेल के जरिए एनएचएआई देशभर के राजमार्ग उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और यात्रा अनुभव को और बेहतर बनाना चाहता है। नई व्यवस्था के तहत कॉल प्राप्त करने और जरूरत वाली जगह पर सहायता भेजने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। कॉल करने वाले की लोकेशन रियल-टाइम में प्राप्त होने से आपातकालीन टीमें तेजी से मौके पर पहुंच सकेंगी। एआई की मदद से विभिन्न भारतीय भाषाओं में की गई कॉल को समझा जा सकेगा।

संपादकीय

निवेशकों का विश्वास

जगदीशन के तीसरा कार्यकाल ना लेने के फैसले को एचडीएफसी बैंक में संस्थागत पुनर्गठन की जरूरत से जोड़ कर देखा गया है। अब बैंक के सामने कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्च मानकों की बहाली की कठिन चुनौती है।

सामान्य स्थितियों में फिर नियुक्ति ना मांगने के एचडीएसी बैंक के महाप्रबंधक और सीईओ शशिधर जगदीशन की घोषणा को उनका निजी फैसला समझा जाता। मगर, जो हालिया पृष्ठभूमि है, उस कारण इस घटना से भारत के इस प्रमुख बैंक के बारे में चर्चित सवालों पर फिर ध्यान गया है। जगदीशन ने अक्टूबर 2026 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति ना मांगने का निर्णय लिया है। इस कदम को बैंक में संचालन संबंधी अनसुलझे मसलों और एचडीएफसी हाउजिंग फाइनेंस कंपनी के साथ उसके विलय के बाद की चुनौतियों के बरकरार रहने का संकेत समझा गया है।

उल्लेखनीय है कि जगदीशन का कार्यकाल बैंक में कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े विवादों से प्रभावित रहा। पूर्व गैर-कार्यकारी अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती के ‘नैतिक चिंताओं’ का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा देने, और महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से संबंधित डिपॉजिट प्रोक्योरमेंट विवाद से बैंक की साख को झटका लगा। क्रेडिट सुइस एटी-1 बॉन्ड सहित विदेशी संपत्तियों की बिक्री के मामले में जोखिम संभालने संबंधी बैंक के मानकों पर सवाल उठे। हालांकि वित्तीय मोर्चे पर बैंक में स्थिरता रही, लेकिन विलय के बाद उसके मुनाफे में आई कमी आई। उससे निवेशकों में उपजे संदेह के कारण शेयर बाजार में बैंक का प्रदर्शन कई वर्षों के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। लंबे समय तक भारतीय रिटेल बैंकिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाने वाले इस बैंक के लिए ये रुझान चिंता का कारण बने हुए हैं।

आम चर्चाओं में बैंक में संचालन संबंधी गलतियों को लेकर कयास लगाए गए हैं। संदेह जताया गया है कि हालिया वर्षों में ऐतिहासिक स्थिरता के रिकॉर्ड से बैंक भटक गया है। इसीलिए जगदीशन के तीसरा कार्यकाल ना लेने के फैसले को बैंक में संस्थागत पुनर्गठन की जरूरत से जोड़ कर देखा गया है। अब बैंक प्रबंधन के सामने जगदीशन के उत्तराधिकारी की अविलंब खोज और कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्च मानकों की बहाली की कठिन चुनौती है। एचडीएफसी की भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए उसके अंदर की घटनाओं पर सबकी निगाह होना लाजिमी है। इसे समझते हुए बैंक के कर्ता-धर्ताओं को निवेशकों का विश्वास फिर हासिल करने के ठोस कदम जल्द उठाने चाहिए।

यूपीआई शुल्क: सुविधाओं का विस्तार या उपभोक्ता पर बोझ?

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में यूपीआई केवल भुगतान का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि वह रोजमर्रा के आर्थिक व्यवहार का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सब्जी वाले से लेकर बड़े कारोबारी तक, टैक्सी से लेकर ऑनलाइन खरीदारी तक और घरेलू लेन-देन से लेकर व्यावसायिक भुगतान तक- यूपीआई ने पैसे के लेन-देन की आदत, गति और भाषा तीनों बदल दी हैं। ऐसे में यूपीआई से जुड़े शुल्क की व्यवस्था केवल बैंकिंग या फिनटेक कंपनियों का कारोबारी विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध उपभोक्ता की आदत, छोटे व्यापार की लागत और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा से है। यहां एक तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। सितंबर 2026 में सरकार ने जो नया ढांचा स्पष्ट किया है, उसके अनुसार व्यक्ति से व्यक्ति यानी पी2पी को यूपीआई भुगतान किसी भी राशि पर नि:शुल्क रहेगा। रू.2,000 तक के व्यापारी भुगतान पर भी एमडीआर नहीं है। रू.2,000 से अधिक के कुछ पी2एम यानी ग्राहक से व्यापारी भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर का प्रावधान किया गया है और रू.75,000 या उससे अधिक के लेन-देन पर प्रति लेन-देन अधिकतम रू. 300 की सीमा रखी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह शुल्क ग्राहक से सीधे वसूल किया जाने वाला लेन-देन शुल्क नहीं है, बल्कि व्यापारी-पक्ष का एमडीआर है।

फिर भी इस बदलाव को केवल 'शुल्क लगा या नहीं लगा' के प्रश्न तक सीमित करना उचित नहीं होगा। असली सवाल यह है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लंबे समय तक टिकाऊ कैसे बनाया जाए और उसकी लागत किसके हिस्से में जाए। यूपीआई की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी सरलता और लगभग बिना लागत की अनुभूति रही है। अगस्त 2026 में यूपीआई पर करीब 24.51 अरब लेन-देन हुए, जिनका कुल मूल्य लगभग रू.29.82 लाख करोड़ रहा। यह आंकड़ा बताता है कि यूपीआई अब किसी वैकल्पिक भुगतान माध्यम की श्रेणी में नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक जीवन के बुनियादी ढांचे में शामिल हो चुका है। यूपीआई के इस विस्तार के पीछे एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी हुआ है। लोगों ने डिजिटल भुगतान को केवल सुविधा नहीं, स्वाभाविक व्यवहार मान लिया है। पहले दस रुपये, पचास रुपये या सौ रुपये के लिए जेब से नकद निकालना सामान्य था आज वही भुगतान मोबाइल से कुछ सेकंड में हो जाता है। जब कोई सेवा वर्षों तक नि:शुल्क उपलब्ध रहती है तो उपभोक्ता उसके पीछे मौजूद तकनीकी, बैंकिंग और साइबर-सुरक्षा लागत को लगभग भूल जाता है। इसलिए बाद में किसी प्रकार का शुल्क या लागत सामने आने पर स्वाभाविक रूप से असहजता पैदा होती है।

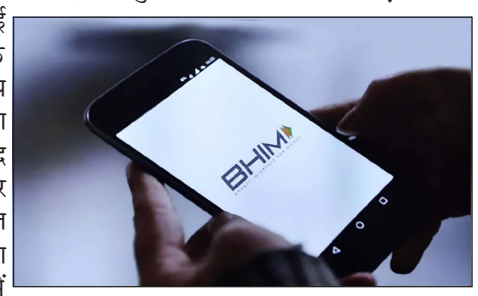

यहीं आधुनिक बाजार व्यवस्था की एक बड़ी विसंगति दिखाई देती है। अनेक डिजिटल और उपभोक्ता सेवाएं पहले मुफ्त, अत्यंत सस्ती या भारी छूट के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं। उपभोक्ता को उस सुविधा का अभ्यस्त बनाया जाता है, बाजार में उसका व्यवहार बदलता है और प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने के बाद लागत की नई संरचना सामने आती है। ओला-उबर जैसी सेवाओं से लेकर ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल सदस्यता और विभिन्न प्लेटफॉर्म सेवाओं तक इस मॉडल के अलग-अलग रूप दिखाई देते हैं। यह कहना उचित नहीं होगा कि हर मामले में यही रणनीति अपनाई जाती है, लेकिन उपभोक्ता के दृष्टिकोण से प्रश्न महत्वपूर्ण है-यदि किसी सेवा की दीर्घकालिक लागत है तो उसकी जानकारी शुरुआत से स्पष्ट क्यों न हो? यूपीआई के मामले में यह प्रश्न और गंभीर है क्योंकि इसके उपयोगकर्ता केवल शहरी मध्यमवर्ग नहीं हैं। छोटे दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू उद्यमी, ग्रामीण उपभोक्ता और पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े लोग भी इसके बड़े हिस्से हैं। सरकार की 2025 की प्रोत्साहन योजना में भी छोटे व्यापारियों के रू.2,000 तक के भीम-यूपीआई भुगतान को शून्य एमडीआर के दायरे में रखते हुए रू.1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ाना और भुगतान ढांचे को मजबूत करना था।

इसलिए शुल्क की किसी भी व्यवस्था का पहला सिद्धांत होना चाहिए-छोटे भुगतान और छोटे कारोबार की रक्षा। रू.100, रू.500 या रू.1,000 के भुगतान पर लागत बढ़ाने वाला मॉडल डिजिटल समावेशन की भावना के विपरीत जा सकता है। इसके विपरीत बड़े व्यावसायिक भुगतान से जुड़ी लागत को अलग तरीके से देखा जा सकता है, बशर्ते शुल्क पारदर्शी, सीमित और पूर्व घोषित हो तथा उसका भार अनुचित रूप से ग्राहक पर न डाला जाए। यहां डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। यूपीआई के व्यापक प्रसार ने कार्ड भुगतान को रोजमर्रा के छोटे भुगतानों में पीछे धकेला है। यदि यूपीआई के कुछ बड़े व्यापारी लेन-देन पर लागत बढ़ती है तो कुछ कारोबारी वैकल्पिक भुगतान माध्यमों की ओर देख सकते हैं। कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या अन्य डिजिटल माध्यम फिर कुछ क्षेत्रों में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। इससे भुगतान बाजार में विविधता बढ़ सकती है, लेकिन यदि उपभोक्ता को हर माध्यम में अलग-अलग शुल्क, सुविधा और शर्तों का सामना करना पड़े तो डिजिटल भुगतान की सरलता कमजोर भी हो सकती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य केवल माध्यम बदलना नहीं, बल्कि उपभोक्ता को बेहतर विकल्प देना होना चाहिए।

दूसरी ओर यूपीआई को मुफ्त बनाए रखने की भी कीमत है। भुगतान प्रणाली को चौबीसों घंटे चलाने के लिए बैंकिंग सर्वर, डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने वाली प्रणालियां, ग्राहक सहायता और तकनीकी उन्नयन पर लगातार खर्च होता है। जैसे-जैसे लेन-देन बढ़ते हैं, वैसे-वैसे विश्वसनीयता और क्षमता पर निवेश की आवश्यकता भी बढ़ती है। सरकार की 2025 की योजना में भी तकनीकी विफलताओं को घटाने और सिस्टम अपटाइम सुधारने को प्रोत्साहन से जोड़ा गया था। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि यूपीआई की हर सेवा हमेशा मुफ्त रहे या नहीं, सवाल यह होना चाहिए कि उसकी लागत का न्यायपूर्ण और पारदर्शी वितरण कैसे हो। सरकार, बैंक, फिनटेक कंपनियां और भुगतान नेटवर्क यदि इस व्यवस्था से आर्थिक लाभ लेते हैं तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा, विश्वसनीयता और नवाचार पर पर्याप्त निवेश हो। शुल्क का उद्देश्य केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि बेहतर डिजिटल भुगतान व्यवस्था के निर्माण से जुड़ा होना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात उपभोक्ता विश्वास की है। डिजिटल अर्थव्यवस्था विश्वास पर चलती है। यदि आज किसी सेवा को 'मुफ्त' बताया जाए और कल अचानक उसकी लागत सामने आए, तो उपभोक्ता में अविश्वास पैदा हो सकता है। इसलिए भविष्य में किसी भी डिजिटल भुगतान व्यवस्था की शुरुआत करते समय उसकी संभावित लागत, शुल्क संरचना और उसे लागू करने की परिस्थितियां पहले से स्पष्ट होनी चाहिए। उपभोक्ता को यह पता होना चाहिए कि कौन-सी सेवा नि:शुल्क है, किस पर लागत है, लागत कौन वहन करेगा और उसका अधिकतम स्तर क्या होगा। भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रहा है। ऐसे समय में यूपीआई की सफलता को केवल लेन-देन की संख्या से नहीं, बल्कि उसकी स्थिरता, सुरक्षा, पहुंच और उपभोक्ता विश्वास से मापना होगा। भारत की विकास-आकांक्षाओं के लिए उत्पादकता, नवाचार और मजबूत डिजिटल आधारभूत ढांचा महत्वपूर्ण हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी भारत की उत्पादकता और नवाचार क्षमता को दीर्घकालिक विकास से जोड़ता है।

यूपीआई शुल्क की बहस इसलिए वास्तव में 'शुल्क बनाम मुफ्त' की बहस नहीं है। यह उस आर्थिक दर्शन की परीक्षा है जिसमें डिजिटल सुविधा आम आदमी तक सस्ती, सरल और सुरक्षित रूप में पहुंचती है।

छोटे भुगतान मुफ्त रहें, छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक भार न पड़े, बड़े व्यावसायिक लेन-देन में लागत की तार्किक व्यवस्था हो, शुल्क की जानकारी पहले से सार्वजनिक हो और उससे प्राप्त संसाधन भुगतान प्रणाली की सुरक्षा व क्षमता बढ़ाने में लगें, ऐसा संतुलन ही टिकाऊ रास्ता हो सकता है। भारत को डिजिटल भुगतान का विस्तार रोकना नहीं, बल्कि उसकी अगली पीढ़ी तैयार करनी है।

इतिहास में जिनके नाम नहीं हैं, उनमें भी नायकों को तलाशें

हम अक्सर चे ग्वेरा और महात्मा गांधी जैसे नायकों की प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने आराम की जिंदगी छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम किया। लेकिन वैसे लोग भी नायक होते हैं, जिन्होंने खुद गरीबी में रहते हुए दूसरों की फिक्र की और उनकी मदद करने के जतन किए। ऐसे लोग मुझे तो बहुत मिले हैं- मजदूर, रिक्शावाले, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य। उनमें से बहुतों ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की होती है। लेकिन मैंने उनमें सहानुभूति, शोषण की समझ और न्याय की गहरी भावना पाई है। आप उन्हें 'सहज-क्रांतिकारी' कह सकते हैं।

क्रांतिकारी से मेरा मतलब यह नहीं है कि वे व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि उन्होंने रूढ़ियों की बेड़ियां तोड़ीं और अपने तरीके से एक नई दुनिया बनाने के लिए काम किया। उनमें से एक थे नियामत अंसारी, जो झारखंड के मणिका प्रखंड में रहते थे। जब मैं उनसे करीब बीस साल पहले मिला था, तब वे अपने दोस्त भूखन के साथ मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। नियामत मुसलमान थे और भूखन आदिवासी, लेकिन दोनों सगे भाइयों जैसे थे। दोनों नियामत की पुरानी, खटारा मोपेड पर बैठकर गांव-गांव जाते थे और मनरेगा के कामों की जांच करते थे।

भूखन और नियामत ने कई भ्रष्ट ठेकेदारों का भंडाफोड़ किया था। जाहिर है, वैसे ठेकेदार उनसे नाराज हो गए और उनसे बदला लेने में लग गए। नियामत और भूखन को झूठे केस में फंसा दिया गया। दोनों को कुछ समय जेल में भी बिताना पड़ा। जेल में उनके साथ जो हुआ, उसके बारे में उनकी बातें तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। वहां रात में कैदियों को टॉयलेट जाने की भी सुविधा नहीं थी। लेकिन जेल से छूटते ही नियामत और भूखन ने फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। ठेकेदार उनकी हत्या की साजिश में लग गए। 2 मार्च 2011 को ठेकेदारों के इशारे पर माओवादियों के एक दस्ते ने नियामत को पीट-पीटकर मार डाला। भूखन ने एक खेत में छिपकर अपनी जान बचाई।

ऐसे 'सहज-क्रांतिकारियों' में कई महिलाएं भी हैं। मणिका में ही मैं ऐसी कई महिलाओं को जानता हूं। उनमें से एक थीं श्यामा सिंह। नियामत की तरह श्यामा भी अत्याचार करने वालों के सामने खड़े होने से नहीं डरती थीं। उन्होंने मणिका की कई महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा दी। 2015 में इन महिलाओं ने बहुत कम पैसे खर्च करके ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव जीतने में श्यामा की मदद की थी। लेकिन ज्यादातर मुखियाओं के विपरीत, श्यामा ने पद का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं किया। पांच साल बाद भी उनका घर लगभग वैसा ही रहा जैसा पहले था, और उनके पास सस्ती स्कूटी के अलावा कोई और वाहन नहीं था।

जब नियामत को आधी रात में पीटा गया था, तब मणिका थाना पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची थी। ऐसे में श्यामा ही हिम्मत करके 10 किलोमीटर दूर अपने घर से निकलकर नियामत को अस्पताल ले जाने के लिए वहां पहुंच गईं। जबकि उस समय श्यामा नियामत से नाराज थीं। लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी भुला दी और उनकी मदद के लिए दौड़ी चली आईं, क्योंकि नियामत उनके साथी थे। 18 जुलाई 2026 को घर में झाड़ू लगाते समय श्यामा को नाग ने काट लिया। कुछ दिन बाद बारिश में उनका अंतिम संस्कार हुआ। गांव के हर घर से कोई न कोई वहां आया।

क्यों पूरी दुनिया अचानक से मानवता के लिए एआई के खतरों पर बात कर रही है?

अमेरिका में हाल ही काफी सारे स्कूलों वाले न्यूयॉर्क सिटी और लॉस एंजेलेस जैसे जिलों ने घोषणा की है कि वे अकादमिक वर्ष 2026-27 में स्टूडेंट्स द्वारा स्कूल के डिवाइसेस पर जनरेटिव एआई के इस्तेमाल पर रोक लगाएंगे। क्योंकि दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को चिंता है कि सावधानी भरे सुरक्षा उपायों के बिना बच्चे चैटजीपीटी जैसे चार साल पुराने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जवाब पाने के शॉर्टकट के तौर पर करने लगेंगे। वे उन जटिल कॉग्निटिव प्रक्रियाओं को बायपास करेंगे, जो सीखने के लिए आवश्यक हैं।

दरअसल, 2003 में- जब मार्क जकरबर्ग ने 'द फेसबुक' का नाम 'फेसबुक' किया ही था, इलॉन मस्क सेंटी-मिलियनेयर नहीं बने थे और सैम ऑल्टमैन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉपआउट नहीं हुए थे- तब ऑक्सफोर्ड के एक ब्रिलियंट फिलॉसफर निक बोस्ट्रॉम ने 'एथिकल इश्यूज इन एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' शीर्षक से एक पेपर प्रकाशित किया था। उस लंबे रिसर्च पेपर में अप्रत्यक्ष चेतावनी दी गई थी कि 'जब हम खुद से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट चीज बनाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा आश्वस्त होना चाहिए कि उसके लक्ष्य हमारे लक्ष्यों के साथ अलाइंड हों।' यहां 'अलाइंड' शब्द पर गौर करें।

सिलिकॉन वैली के सबसे बेहतरीन दिमाग पहले ही एजीआई डिजाइन कर चुके हैं। यानी, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। बुनियादी तौर पर एजीआई इंसान के किसी भी इंटेलेक्चुअल काम को कर सकता है। ऐसे मॉडल इंसानी राइटिंग की नकल करने के लिए ट्रेंड किए गए हैं। कई लोग तर्क देते हैं कि वे क्रिएटिव नहीं होंगे, इसलिए वास्तव में इंटेलिजेंट भी नहीं होंगे। लेकिन धीरे-धीरे इन एआई को दिए जा रहे टेस्ट चौंकाने वाले नतीजे दे रहे हैं। यह सिर्फ सदियों से इंसानों को उलझाए रखने वाली मैथ्स प्रॉब्लम्स को हल करने तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि क्या उन्होंने 'आरएसआई' विकसित कर लिया है?

अब यह 'आरएसआई' क्या है? इसका मतलब है रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट। विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे ही किसी कंप्यूटर के पास अपना एजीआई आ जाता है तो वह एचआई (ह्यूमन इंटेलिजेंस) का कम इस्तेमाल करता है। प्रोग्रामर्स के बजाय वह अपना सक्सेसर डिजाइन करने के लिए एजीआई इस्तेमाल करता है। फिर वह सक्सेसर अपना सक्सेसर बनाता है। प्रतिभाशाली लोगों को चिंता है कि देर-सबेर कम से कम आईक्यू के क्षेत्र में तो एक इंटेलिजेंस विस्फोट जरूर होगा। और हम इंसान उनके लिए वैसे ही बन जाएंगे, जैसे बच्चे हमारे लिए हैं।

अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या हम एआई को यह नहीं बता सकते कि वह हमें न मारे या हमारे सामने बच्चों जैसा रहे? दुनिया भर के प्रोग्रामर्स ठीक इसी विचार पर काम कर रहे हैं। वे इस प्रक्रिया को हमारी थॉट प्रोसेस के साथ 'अलाइनमेंट' कह रहे हैं और यही निक बोस्ट्रॉम ने 23 साल पहले लिखा था।

अब एआई सेफ्टी रिसर्चर्स एलिएजर युडकोव्स्की और नेट सोरेस की 2025 में रिलीज हुई बुक 'इफ एनीवन बिल्ड्स इट, एवरीवन डाइज' ठीक यही चेतावनी देती है। यह आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस मशीनें बनाने के खतरों को बताती है, जो किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा स्मार्ट होंगी। किताब को तीन मुख्य हिस्सों में बांटकर बताया गया है कि लेखक क्यों मानते हैं कि एडवांस्ड एआई मानवता को खत्म कर देगा।

मोदी को 'धमकाना' ट्रंप को पड़ा भारी! रूसी तेल पर अमेरिका के नए दांव का भारत ने दिया करारा जवाब

कहने को तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शायद वह मोदी को अब तक अच्छे से जान ही नहीं पाए हैं। देखा जाये तो जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते नहीं, वह अक्सर धमकियों, प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के सहारे उन्हें झुकाने का सपना देखते हैं। लेकिन मोदी का संकल्प साफ है कि भारत के हितों से समझौता नहीं होगा और देश को किसी विदेशी दबाव के आगे झुकने नहीं देना है। उनके हर फैसले में यही दृढ़ता दिखाई देती है। दूसरी ओर, ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही भारत पर दबाव बनाने के लिए शुल्क, व्यापारिक दबाव और रूस से तेल खरीद बंद कराने जैसी तमाम कोशिशें कीं, लेकिन नई दिल्ली ने हर बार अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च रखा। अब अमेरिका एक बार फिर टैरिफ रूपी आर्थिक हथियार लेकर मैदान में उतरा है, लेकिन मोदी सरकार ने भी बिना देर किए वाशिंगटन को साफ संदेश दे दिया है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हित किसी विदेशी दबाव की कीमत पर तय नहीं होंगे। पूर्वयूरोपीय

हम आपको बता दें कि जिस विधेयक को अमेरिकी कांग्रेस में पहली बार अप्रैल 2025 में पेश किया गया था, वह करीब डेढ़ साल तक अमेरिकी राजनीति और ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं के बीच अटका रहा। लेकिन इस महीने यानि सितंबर 2026 में तस्वीर अचानक बदल गई। भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सक्रिय कूटनीतिक भागीदारी के कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रूस और ईरान पर नए प्रतिबंधों वाला विधेयक पारित कर दिया। घटनाक्रम का समय भले ही संयोग हो, लेकिन संदेश बेहद स्पष्ट है कि वाशिंगटन रूस से जुड़े देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अब शुल्क को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने को तैयार है।

लेकिन भारत ने भी अमेरिका को उसी क्षण जवाब दे दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत बदलती बाजार परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा खरीदता रहेगा। इतना ही नहीं, नई दिल्ली ने अमेरिका को याद दिलाया कि इस कदम के भारत-अमेरिका संबंधों के साथ-साथ पूरे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में अमेरिकी पक्ष को पहले ही उच्च स्तर पर स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि भारत अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। यानी अमेरिका शुल्क की धमकी दे सकता है, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा की कीमत पर किसी विदेशी दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल, जिस विधेयक को अब 'लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम 2026' कहा जा रहा है, उसकी कहानी डेढ़ साल पुरानी है। अप्रैल 2025 में लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने रूस के खिलाफ कड़े प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिबंधों की पहल की थी। इसके बाद लंबे समय तक इसे कांग्रेस और प्रशासन के बीच समर्थन जुटाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। जुलाई 2026 में व्हाइट हाउस से सहमति बनने के बाद इसकी राह खुली। अगस्त में सीनेट ने इसे 86 के मुकाबले 11 मतों से पारित किया और 16 सितंबर को प्रतिनिधि सभा ने 262 के मुकाबले 159 मतों से इसे मंजूरी दे दी।

यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदारों पर सौ प्रतिशत तक शुल्क लगाने का अधिकार देता है। भारत और चीन इसके निशाने पर हैं। इसके पीछे अमेरिकी रणनीति रूस की ऊर्जा आय को चोट पहुंचाने की है, ताकि यूक्रेन युद्ध के लिए मास्को को मिलने वाले आर्थिक संसाधनों पर दबाव बनाया जा सके। विधेयक में रूस के ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों के साथ-साथ प्रतिबंधों से बचने वाले उसके जहाजी बेड़े पर भी शिकंजा कसने का प्रावधान है। लेकिन अमेरिका शायद यह भूल रहा है कि भारत रूस से तेल किसी राजनीतिक एहसान के लिए नहीं खरीद रहा। भारत की जरूरत है सस्ती, विश्वसनीय और लगातार उपलब्ध ऊर्जा। 2022 में रूस भारत के लिए कोई बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता नहीं था। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप द्वारा रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए जाने से रूस का कच्चा तेल भारी छूट पर उपलब्ध हुआ और भारत ने अपने आर्थिक हित में इसे खरीदना शुरू किया। इसके बाद रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। वित्त वर्ष 2026 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूसी हिस्सेदारी 30.3 प्रतिशत रही और करीब 134.7 अरब डॉलर के कुल आयात में रूस से आने वाले तेल की कीमत 40.8 अरब डॉलर रही। जुलाई 2026 में तो भारत के आयातित तेल में रूसी हिस्सेदारी आधे से भी ज्यादा पहुंच गई। इतिहास

इसके अलावा, आज वैश्विक परिस्थितियों को देखें तो वह भी सामान्य नहीं हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध और आपूर्ति संकट ने तेल बाजार को बुरी तरह प्रभावित किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधाएं हैं और वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत भी दबाव में हैं। भारत 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन रूस और पश्चिम एशिया उसकी ऊर्जा सुरक्षा के मुख्य आधार बने हुए हैं। ऐसे समय में अचानक रूसी तेल बंद करना केवल रूस के खिलाफ फैसला नहीं होगा, बल्कि भारत की अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकता है।

यही कारण है कि पिछले साल अमेरिकी दंडात्मक शुल्क भी भारत को रूसी तेल से पूरी तरह दूर नहीं कर सके। भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल की खरीद में बड़ी कटौती तब की जब रूस की प्रमुख तेल कंपनियों पर सीधे प्रतिबंध लगाए गए और व्यापार करना कठिन हो गया। लेकिन जैसे ही पश्चिम एशिया में आपूर्ति संकट गहराया, भारत ने फिर रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी। जुलाई में रूसी तेल की खरीद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इससे एक बात साफ होती है कि भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा कोई सौदेबाजी का विषय नहीं है।

यहां इस पूरे घटनाक्रम का सामरिक महत्व सामने आता है। अमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहता है। जबकि रूस भारत की ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। चीन भी रूसी ऊर्जा का बड़ा खरीदार है। साथ ही भारत एक साथ अमेरिका, रूस, चीन, ईरान तथा पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपने हितों का संतुलन साध रहा है। ऐसे में नई दिल्ली के सामने चुनौती किसी एक खेमे में जाने की नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बचाए रखने की है। विधानशाखा

इसके अलावा, ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी की पुतिन और जिनपिंग के साथ बढ़ती कूटनीतिक निकटता ने जिस बदलती विश्व व्यवस्था की तस्वीर अमेरिका के सामने रखी, उसके कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी कांग्रेस का रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने वाला कदम कई सवाल खड़े करता है। सवाल उठता है कि क्या वाशिंगटन को यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि दुनिया अब उसकी शर्तों पर नहीं चलती? देखा जाये तो भारत, रूस और चीन का एक मंच पर आना और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था तथा संप्रभु समानता की वकालत करना उस अमेरिकी वर्चस्ववादी सोच के लिए सीधी चुनौती है, जिसमें लंबे समय से आर्थिक ताकत को कूटनीतिक दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन बदलती दुनिया का संदेश साफ है। भारत सहित उभरती शक्तियां अब अपने राष्ट्रीय हितों का फैसला किसी बाहरी राजधानी के इशारे पर नहीं करेंगी।

खैर...अब गेंद ट्रंप के पाले में है। अमेरिकी कांग्रेस ने उन्हें सौ प्रतिशत तक शुल्क लगाने की शक्ति दे दी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सौ प्रतिशत शुल्क स्वत: लागू हो गया। अंतिम निर्णय ट्रंप को करना है। शुल्क कितना होगा, किन वस्तुओं पर लागू होगा और कब लागू होगा, इन सबका असर भारत-अमेरिका व्यापार पर पड़ेगा। भारत का रुख स्पष्ट है कि ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं होगा, विकल्पों का विस्तार जारी रहेगा, अमेरिका से बातचीत जारी रहेगी और राष्ट्रीय हितों पर कोई एकतरफा समझौता नहीं होगा। अमेरिकी शुल्क चाहे जितना बड़ा हो, भारत के लिए असली सवाल किसी एक देश को खुश करना नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्वायत्तता सुरक्षित रखना है। विदेश मंत्रालय पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। भारत अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

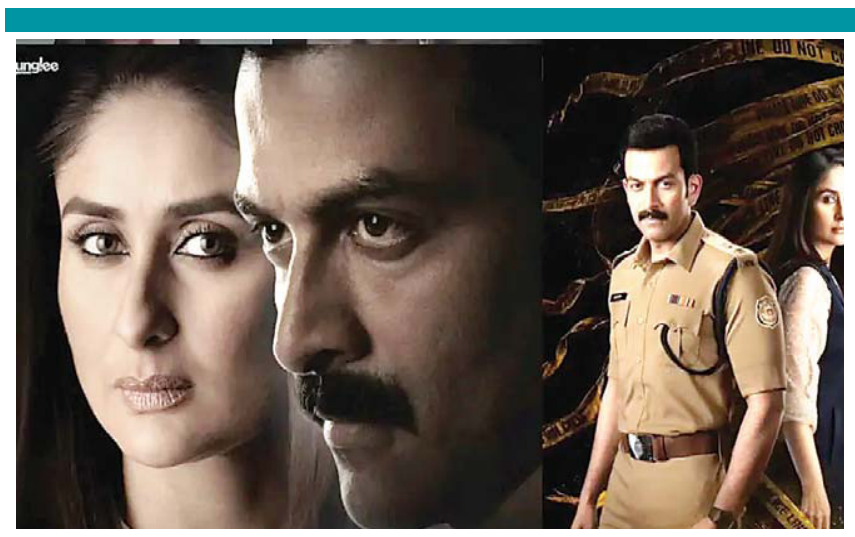

फिल्म दायरा में करीना-पृथ्वीराज की एक्टिंग में कौन पड़ा भारी?

मेघना गुलजार की 'दायरा' एक ऐसे पुलिस एनकाउंटर की कहानी है, जो अपराध से ज्यादा कानून और इंसाफ के बीच की सीमा पर सवाल उठाती है। जब गंभीर अपराध के आरोपियों को अदालत के फैसले से पहले पुलिस कार्रवाई में मार दिया जाता है, तो जनता इसे इंसाफ मानती है, लेकिन जांच कुछ और ही कहानी सामने लाती है। फिल्म इसी उलझन को गंभीरता से सामने रखती है। फिल्म में करीना कपूर खानऔर पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में है।फिल्म की कहानी एक युवती के गैंगरेप और हत्या के आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर से शुरू होती है। इस कार्रवाई के बाद जनता में इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। मामले की जांच एसआईटी को सौंपी जाती है, जिसकी कमान डीसीपी अजोनी कोहली यानी करीना कपूर खान के हाथ में है। दूसरी तरफ डीसीपी रमन कुमार यानी पृथ्वीराज सुकुमारन हैं, जो एनकाउंटर करने वाली टीम का नेतृत्व करते हैं। अजोनी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, एनकाउंटर की आधिकारिक कहानी पर सवाल उठने लगते हैं।यही फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा है। अजोनी का मानना है कि पुलिस को हर हाल में कानून के दायरे में रहना चाहिए। वहीं रमन अपराध की गंभीरता और पीड़ित परिवार की स्थिति को देखते हुए अपने तरीके को सही मानता है। फिल्म किसी एक पक्ष को पूरी तरह सही साबित करने की कोशिश नहीं करती। वह पूछती है कि अगर न्याय मिलने में वर्षों लग जाएं, तो क्या लोगों से हमेशा इंतजार करने की उम्मीद की जा सकती है? और अगर पुलिस खुद फैसला लेने लगे, तो कानून और जवाबदेही का क्या होगा? यह बहस दिलचस्प है, हालांकि स्क्रीनप्ले अजोनी के पक्ष को उतनी भावनात्मक मजबूती नहीं देता, जितनी रमन के गुस्से और सोच को मिलती है।पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म में खास तौर पर प्रभावित करते हैं। रमन के भीतर का गुस्सा और अपनी कार्रवाई को सही मानने का विश्वास उनके अभिनय में साफ नजर आता है। उनका किरदार न तो पूरी तरह नायक है और न खलनायक, और यही उसकी दिलचस्पी बढ़ाता है। करीना कपूर खान अजोनी के किरदार में अच्छी हैं, लेकिन कुछ जगह उनका अंदाज फिल्म के गंभीर और यथार्थवादी माहौल से थोड़ा अलग महसूस होता है। क्षिती जोग, जितेंद्र जोशी और तृप्ति खामकर जैसे कलाकार भी अपने किरदारों में प्रभाव छोड़ते हैं।फिल्म का पहला हिस्सा काफी संयमित गति से आगे बढ़ता है। जांच की प्रक्रिया और पूछताछ को विस्तार दिया गया है, जिससे कहानी में वास्तविकता आती है, लेकिन इसी वजह से कुछ दर्शकों को शुरुआत थोड़ी लंबी लग सकती है। दूसरे हाफ में कहानी ज्यादा पकड़ बनाती है और घटनाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं। हालांकि क्लाइमैक्स पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया दिलचस्प बनी रहती है।हां। फिल्म की खासियत इसका कोई सीधा संदेश देना नहीं, बल्कि सवाल छोड़ना है। क्या अपराध की गंभीरता कानून से ऊपर हो सकती है? क्या पुलिस को अपराधियों को तुरंत सजा देने का अधिकार मिलना चाहिए? और जब सिस्टम पर लोगों का भरोसा कम होने लगे, तो क्या शॉर्टकट को इंसाफ कहा जा सकता है? फिल्म इन सवालों के आसान जवाब नहीं देती और दर्शक को खुद अपनी राय बनाने की जगह देती है।

क्या साउथ सिनेमा को अपनाने का समय आ गया...?

इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में साउथ सिनेमा का क्रेज हर ओर छाया हुआ है. ऐसे में भारतीय सिनेमा भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है. जब से फिल्म बाहुबली ने 'पैन-इंडिया' फिल्म के विचार की पेशकश की है तभी से दर्शकों ने क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को एक राष्ट्रीय तौर पर अपना लिया है. ये बात जगजाहिर है कि पंजाबी और बंगाली सिनेमा को अभी तक साउथ सिनेमा की तरह इंडस्ट्री में अपनाया नहीं गया है. साउथ की फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बना लेती हैं. बहरहाल, निश्चित रूप से ही दक्षिणी राज्यों को एक ऐसी भाषा का स्थान प्राप्त है जिसे आसानी से ना समझ पाने के बावजूद हर कोई समझ रहा है. ये दौर हिंदी फिल्मों से कहीं ज्यादा साउथ फिल्मों का है. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म साउथ रीमेक्स ने बॉलीवुड को बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ दिया. फिल्म आरआरआर, पुष्पा और केजीएफ चैप्टर 2, साउथ ब्लॉकबस्टर बाहुबली के एक नए पौराणिक डेमोग्राफिक के निर्माण पर बनी हैं **फिल्म आरआरआर** रिलीज होने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार जूनियर एनटीआर ने हिंदी फिल्मों की कमियों को उजागर करते हुए कहा था कि फ्मुझे लगता है कि पिछली बार एक मसाला फिल्म में दो अभिनेताओं ने एक साथ धमाकेदार किरदार निभाया था. वो फिल्म थी साल 1995 में रिलीज हुई शाहरुख और सलमान की करण अर्जुन. इसके अलावा अपने इंटरव्यू में अभिनेता ने क्रॉस पॉलीनेशन का भी मुद्दा उठाया था. **जूनियर एनटीआर ने उठाई थी क्रॉस पॉलीनेशन की बात** : वहीं, अभिनेता ने जिस क्रॉस-पॉलिनेशन की बात की है वह पारंपरिक सीमाओं के बाहर के लोगों के साथ मदद के बारे में भी है. धनुष और रजनीकांत जैसे दक्षिणी राज्यों के अभिनेताओं ने बॉलीवुड में कमाल का अभिनय किया है. इसके बावजूद वो इंडस्ट्री पर एक नॉर्म प्रभाव ही छोड़ पाए. इसकी वजह यह है कि उन्हें हिंदी सिनेमा में अपनी सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखने का मौका ही नहीं दिया गया.**हिंदी फिल्म निर्माण के इकोसिस्टम में है गड़बड़ी**: रजनीकांत जब अपने स्टारडम की ऊंचाई पर थे तो अनगिनत फिल्म निर्माताओं ने उन्हें फिल्मों में अपने हिसाब से कास्ट किया, लेकिन लीड रोल के बावजूद हिन्दी सिनेमा के दर्शकों के साथ वो कभी तालमेल नहीं बिठा पाए. यही बात अभिनेता आर माधवन के लिए भी कही जा सकती है. क्योंकि, और अभिनेताओं की तरह माधवन के पास फैन फॉलोइंग की भी कमी है. दरअसल इस समस्या की सीधी सी वजह हिंदी फिल्म निर्माण का इकोसिस्टम है. जो दक्षिण राज्यों के फिल्म इंडस्ट्री से मदद करने के बजाय उनकी फिल्मों का रीमेक ही बनाना चाहता है. बॉलीवुड फिल्मों में साउथ एक्टर्स को बॉलीवुड एक्टर के रूप में कास्ट किया जाता है. बल्कि अगर सही से देखा जाए तो कहानियों को ही इस अंदाज में लिखना चाहिए जो साउथ अभिनेताओं को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की इजाजत दे.**कमल हासन ने उठाया था क्रॉस-पॉलिनेशन का मुद्दा** : दूसरी ओर साउथ में भी ऐसी ही मानसिकता है. लेकिन, इस समय बॉलीवुड को इसकी ज्यादा जरूरत है. बात करें फिल्म द फैमिली मैन के मुथु (रवींद्र विजय) और अज्जी (सामंथा) के किरदार की तो ये इस बात का सबसे बड़ा और सटीक सबूत हैं. कमल हासन ने एक बार क्रॉस-पॉलिनेशन की इस स्पिरिट को जोरों शोरों के साथ उठाया था लेकिन उसका नतीजा ये रहा कि साउथ इंडस्ट्री से उन्हें बाहर कर दिया गया. हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री की रचनात्मकता काफी हद तक अपनी सीमाओं में जकड़ी हुई है. इस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडस्ट्र की कुछ सफल फिल्मों ने अभी तक फैंस के आदान-प्रदान का अनुभव नहीं किया है. जो अक्सर साउथ की फिल्मों में देखने को मिल जाता है।

पुष्पा द राइज के अगले सीक्वल में साथ काम करेंगे ये एक्टर्स: मलयालम न्यू वेव फिल्मों का सबसे लोकप्रिय चेहरा फहाद फासिल ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा- द राइज के अगले सीक्वल में तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन के साथ काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस तरह के परफारमेंस और सांस्कृतिक विचार-धारा का जब आदान-प्रदान होता है तो फिल्म स्टूडियो एक्सक्यूटिव के कांसेप्ट और आइडियाज से कहीं आगे निकल कर सिनेमा को आगे बढ़ाने का काम करता है। बॉलीवुड जिन परेशानियों से गुजर रहा है वह केवल किसी सब्जेक्ट या स्टार पावर के बारे में नहीं है बल्कि टेक्निकल क्रफ्ट और अस्थेटिक ट्रीटमेंट के बारे में भी है. दक्षिणी राज्यों के निर्देशकों और तकनीशियनों ने जिस तरह की अपील और विजुअल ऑथोरिटी दिखाई है उससे यह कहा जा सकता है कि वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा आगे है. इसका प्रमाण केजीएफ- चैप्टर 2 और आरआरआर है.

क्या बॉलीवुड की विचारधारा में होगा बदलाव ? वहीं, बात करें बॉलीवुड के कट्टर फिल्म निर्माताओं के बारे में तो दावा किया जा सकता है कि बॉलीवुड टॉलीवुड की तुलना में कहीं ज्यादा 'सार्थक' काम करता है. निर्माताओं का मानना है कि बॉलीवुड सिनेमाघरों में अपनी पहचान खो रहा है. साथ ही, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आगे चल रहा है. इन सब सवालों का जवाब केवल संरचनात्मक परिवर्तनों से ही मिल सकता है. बॉलीवुड को ये इस बात को मानना होगा कि शायद भारत की सबसे धमाकेदार और महत्वपूर्ण पर्सनालिटी साउथ सिनेमा में काम कर रही है. इस सच्चाई को मानने के बाद ही बॉलीवुड खुद को इस जंग में बचा सकता है. इसके पहले कई बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कई बाहरी लोगों को खुद से दूर किया है लेकिन अब उनका स्वागत होना चाहिए. बहरहाल, यह पसंद आपकी होनी चाहिए कि आप बदलाव के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं या फिर इस मौजूदा हालात के साथ संतुष्ट हैं।

एक्ट्रेस बनने से पहले सोनम ने वेट्रेस का काम किया था

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर 9 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. सोनम के लिए उनका ये बर्थडे काफी स्पेशल होने वाला है. क्योंकि वे मां बनने वाली हैं. मॉमी टू बी सोनम कपूर के घर में बहुत जल्द किलकारियां गूंजने वाली हैं. सोनम की पर्सनल लाइफ हिट रही है. मगर उनकी प्रोफेशनल लाइफ सक्सेसफुल नहीं रही. सोनम कपूर अभी तक 20 फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. आपको जानकर हैरानी होगी इनमें से उनकी 5-6 फिल्मों को ही सक्सेस मिली है. बाकी सभी फिल्में पिटी हैं. जो 6 फिल्में चलीं वो भी सोनम की एक्टिंग के बलबूते नहीं बल्कि मेल स्टार या उम्दा कहानी की बदौलत चली. ऐसे में सोनम कपूर का करियर किस कदर खतरे में है उसका आप अच्छे से आंकलन कर सकते हैं. सोनम अच्छी एक्ट्रेस नहीं हैं. उनकी एक्टिंग में कमी आसानी से निकाली जा सकती है. फैक्ट ये भी है कि सोनम कपूर कभी एक्ट्रेस ही नहीं बनना चाहती थीं. जी हां. आपने सही सुना. सोनम कपूर ने कभी हीरोइन बनने का सपना नहीं देखा था. वो डायरेक्टर संजय लीला भंसाली थे जिन्होंने सोनम पर एक्टिंग करने का दवाब डाला. सोनम को सुझाव दिया कि वो एक्ट्रेस बनें. सोनम ने संजय लीला भसाली की ही फिल्म सांवरिया से डेब्यू किया था. जो कि बुरी तरह पिटी. इस मूवी के लिए सोनम ने 2 साल में 35 किलो वजन घटाया था. कम लोग जानते होंगे कि एक्ट्रेस बनने से पहले सोनम कपूर ने वेट्रेस का काम किया था. हालांकि उनकी ये जॉब 1 हफ्ते ही चली. 15 साल की उम्र में सोनम कपूर ने बतौर वेट्रेस पहली नौकरी की थी. ये बात तब की है जब सोनम सिंगापुर में स्टडी कर रही थीं. सिंगापुर में पढ़ाई के दौरान सोनम की रानी मुखर्जी से मुलाकात हुई थी. तब सोनम ने रानी को बताया था कि वो फिल्ममेकर बनना चाहती हैं. फिर अनिल कपूर ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपनी बेटी का नाम भंसाली को सुझाया था. सोनम ने बॉलीवुड में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भंसाली के साथ ही काम किया था. ब्लैक फिल्म में भी सोनम ने भंसाली को असिस्ट किया था. सोनम को बॉलीवुड में सक्सेस नहीं मिली. उनकी हिट फिल्मों में भाग मिल्खा भाग, नीरजा, पैडमैन, वीरे दी वेडिंग, संजू, रांझणा शामिल हैं. सोनम कपूर की अपकमिंग फिल्मों में AK vs AK और ब्लाइंड शामिल हैं. फिलहाल सोनम कपूर प्रेग्नेंसी फेज को एंजॉय कर रही हैं. सोनम कपूर मां बनने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. सोशल मीडिया पर उनकी बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें वायरल होती हैं।

35 साल बाद आई सेंसर बोर्ड की नई गाइडलाइंस, अब वॉर्निंग के साथ ही फिल्मों में दिखाए जाएंगे ऐसे सीन्स

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सेंसर बोर्ड के सदस्यों में बदलाव के बाद अब नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई। ऐसा 35 साल बाद हुआ है।साल 1991 में सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस जारी की गई थी। अब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इनमें से एक बदलाव वॉर्निंग के साथ ड्रग्स संबंधित सीन्स दिखाने हैं।

सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस में ज्यादातर पुराने ही नियम हैं, लेकिन इसमें एक नया नियम जोड़ा गया है। यह नया नियम नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों (सब्सटेंस) से जुड़ा है। अब जिस भी फिल्मों नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों (सब्सटेंस) का सेवन और तस्करी से संबंधित कोई कंटेंट दिखाएंगे जाएंगे तो उनके साथ एक यह चेतावनी दी जाएगी कि %अवैध नशीले पदार्थ सेहत को बर्बाद करते हैं और जेल की सजा दिलाते हैं। ड्रग्स को ना कहें%। यह एक जरूरी चेतावनी होगी।

वहीं, 35 साल पहले यानी 1991 में नियम था कि फिल्मों में ड्रग एडिक्शन को ग्लोरिफाई या जस्टिफाई करने वाले सीन्स को नहीं दिखाया जाएगा।

सेंसर बोर्ड की नई गाइडलाइंस में एज मार्कर में तीन और शामिल किए गए हैं। यह नए एज मार्कर्स, 7+, UA 13+ और UA 16+ है। इनके तहत बताई गई उम्र से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता की देखरेख की सलाह दी गई है।

CBFC के चेयरपर्सन शशि शेखर वेम्पति ने एक्स हैंडल पर एज मार्कर्स को ल लेकर लिखा है, फिल्म निर्माताओं को प्रमोशनल मटेरियल्स में इन मार्कर्स को साफ तौर पर दिखाना चाहिए, ताकि बच्चों को फिल्म दिखाने से पहले दर्शक इन्हें अच्छी तरह समझ सकें।

दूसरे बच्चे के जन्म से पहले फिर सिद्धिविनायक पहुंचीं दीपिका

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। इसी बीच दीपिका और रणवीर एक बार फिर भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। इस दौरान रणवीर के माता-पिता भी उनके साथ नजर आए। मंदिर से दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।खास बात यह है कि दीपिका ने अपनी पहली प्रेग्नेंसी के दौरान भी बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंची थीं। सितंबर 2024 में बेटी दुआ के जन्म से कुछ दिन पहले दीपिका, रणवीर और उनका परिवार सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचा था। उस समय दीपिका ने हरे रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी। मंदिर से सामने आईं उनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं।इसके कुछ ही दिन बाद दीपिका और रणवीर माता-पिता बने थे। दीपिका ने अपनी बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने दुआ रखा है। अब जब कपल अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहा है, दोनों एक बार फिर सिद्धिविनायक मंदिर बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं।

बक्सर में 22 सितंबर को लगेगा बड़ा रोजगार कैंप, 100 पदों पर होगी मौके पर भर्ती; 10वीं, 12वीं, स्नातक और आईटीआई पास युवाओं के लिए नौकरी का अवसर

टेलीकॉलर, हेल्पर और टेक्नीशियन के पदों पर होगी नियुक्ति, 18 से 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी ले सकेंगे हिस्सा; 10 हजार से 25 हजार रुपये तक प्रतिमाह वेतन

बक्सर (संवाददाता)। जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। जिला नियोजनालय, बक्सर की ओर से आगामी 22 सितंबर 2026 को रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार शिविर में निजी कंपनी एक्सपर्ट मैनपावर सर्विस द्वारा विभिन्न पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का मौके पर चयन किया जाएगा। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह शिविर खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कुल 100 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जिला नियोजन पदाधिकारी, बक्सर से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजगार शिविर में टेलीकॉलर, हेल्पर और टेक्नीशियन के कुल 100 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अलग-अलग पदों के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता और कार्यक्षमता के आधार पर चयन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि और समय पर रोजगार शिविर स्थल पर पहुंचकर चयन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। कंपनी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को उनके पद, योग्यता और कार्य के अनुसार प्रतिमाह 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक वेतन दिया जाएगा। इस प्रकार अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार पाने का अवसर उपलब्ध रहेगा। जिला नियोजनालय की ओर से युवाओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि को आवश्यक दस्तावेजों के साथ रोजगार शिविर में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

इस रोजगार शिविर में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। भर्ती प्रक्रिया में 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु वाले अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे। ऐसे युवा जो निर्धारित आयु सीमा में आते हैं और संबंधित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, वे रोजगार शिविर में शामिल होकर कंपनी के समक्ष अपना आवेदन और योग्यता प्रस्तुत कर सकते हैं। युवाओं को सलाह दी गई है कि रोजगार शिविर में पहुंचने से पहले वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, ताकि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। मौके पर कंपनी द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता और पद के अनुरूप चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जॉब कैंप में शामिल होने के लिए अलग-अलग पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। 10वीं, 12वीं, स्नातक तथा आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस रोजगार शिविर में भाग ले सकते हैं। यानी जिले के ऐसे युवा जिन्होंने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक या तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है, उनके लिए निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। विशेष रूप से तकनीकी योग्यता रखने वाले आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं के लिए टेक्नीशियन के पद पर रोजगार का अवसर महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं अन्य शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी टेलीकॉलर और हेल्पर समेत उपलब्ध पदों के लिए चयन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे।

इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों का कार्यस्थल केवल बक्सर तक सीमित नहीं रहेगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को बक्सर, बिहार के अन्य स्थानों अथवा गुजरात में रोजगार का अवसर मिल सकता है। इसलिए जो अभ्यर्थी अपने गृह जिले से बाहर जाकर रोजगार करने के इच्छुक हैं, वे भी इस रोजगार शिविर में भाग लेकर उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यस्थल, पद, वेतन और अन्य नियुक्ति संबंधी शर्तों की जानकारी संबंधित नियोजक कंपनी द्वारा अभ्यर्थियों को दी जाएगी। अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के दौरान कंपनी से नौकरी से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेने की सलाह दी गई है।

जिला नियोजनालय की ओर से आयोजित यह रोजगार शिविर 22 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे से शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के भीतर रोजगार शिविर स्थल पर पहुंचना होगा। रोजगार शिविर का आयोजन संयुक्त श्रम भवन, आईटीआई मैदान, बक्सर स्थित जिला नियोजनालय कार्यालय परिसर में किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की भीड़ और दस्तावेजों से जुड़ी किसी परेशानी से बचने के लिए समय से पहले आयोजन स्थल पर पहुंचें। शिविर में कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध पदों और चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी जाएगी तथा योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

बक्सर जिले में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए 22 सितंबर का यह रोजगार शिविर महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है। एक ही स्थान पर 100 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया होने से अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का मौका मिलेगा। खासकर 10वीं, 12वीं, स्नातक और आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं के लिए अलग-अलग योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों में रोजगार की संभावना रहेगी। जिला नियोजनालय की ओर से आयोजित इस शिविर का उद्देश्य रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को नियोजक कंपनियों से जोड़ना है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान का ध्यान रखते हुए आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचना चाहिए।

रोजगार शिविर का आयोजन 22 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जिला नियोजनालय कार्यालय परिसर, संयुक्त श्रम भवन, आईटीआई मैदान, बक्सर में होगा। भर्ती में शामिल होने के इच्छुक 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 10वीं, 12वीं, स्नातक और आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपना निबंधन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही बायोडाटा और आधार कार्ड लेकर निर्धारित समय पर पहुंचना होगा।

कुल मिलाकर, बक्सर जिला नियोजनालय की ओर से आयोजित इस रोजगार शिविर में 100 पदों पर भर्ती का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। टेलीकॉलर, हेल्पर और टेक्नीशियन के पदों पर चयनित युवाओं को योग्यता और पद के अनुसार 10 हजार से 25 हजार रुपये तक प्रतिमाह वेतन मिल सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे पात्र अभ्यर्थी 22 सितंबर को जिला नियोजनालय परिसर में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

बायोडाटा और आधार कार्ड लेकर पहुंचना होगा

रोजगार शिविर में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपना अद्यतन बायोडाटा साथ लेकर जाना होगा। इसके अलावा पहचान के लिए आधार कार्ड भी साथ रखना जरूरी होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता से जुड़े आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतियां भी साथ रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी योग्यता से संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर सकें। बायोडाटा में अभ्यर्थी का नाम, संपर्क नंबर, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, अनुभव और अन्य जरूरी जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए। इससे कंपनी के प्रतिनिधियों को अभ्यर्थी की योग्यता समझने और संबंधित पद के लिए चयन करने में सुविधा होगी।

नियुक्ति की शर्तों के लिए संबंधित कंपनी होगी जिम्मेदार

जिला नियोजनालय ने बताया है कि रोजगार शिविर के माध्यम से अभ्यर्थियों और नियोजक कंपनी के बीच रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने में सहायता की जाएगी। नियुक्ति से संबंधित शर्तों, कार्य की प्रकृति, वेतन, कार्यस्थल, सेवा की अवधि तथा अन्य प्रक्रियाओं के लिए संबंधित नियोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसका अर्थ है कि अंतिम नियुक्ति और उससे जुड़ी शर्तें कंपनी तथा चयनित अभ्यर्थी के बीच तय होंगी। अभ्यर्थियों को चयन के दौरान नौकरी से जुड़ी सभी शर्तों को अच्छी तरह समझने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

जिला नियोजनालय में निबंधन कराना जरूरी

रोजगार शिविर में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का जिला नियोजनालय में निबंधन होना अनिवार्य बताया गया है। जिन युवाओं ने पहले से जिला नियोजनालय में अपना निबंधन करा रखा है, वे निर्धारित तिथि को आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में शामिल हो सकते हैं। वहीं जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक जिला नियोजनालय में अपना निबंधन नहीं कराया है, वे नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं। निबंधन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थी रोजगार शिविर में भाग ले सकेंगे। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे निबंधन की प्रक्रिया समय रहते पूरी कर लें, ताकि रोजगार शिविर के दिन किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

रोजगार शिविर में नहीं देना होगा कोई शुल्क

जिला नियोजनालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस रोजगार शिविर में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। रोजगार शिविर में प्रवेश और भागीदारी पूरी तरह नि:शुल्क रहेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन, प्रवेश अथवा चयन प्रक्रिया में शामिल होने के नाम पर कोई राशि नहीं देनी है। अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि भर्ती या नियुक्ति के संबंध में कोई शुल्क अथवा अन्य शर्त बताई जाती है, तो उसकी जानकारी संबंधित नियोजक से स्पष्ट रूप से प्राप्त करें। जिला नियोजनालय ने अपनी भूमिका को केवल सुविधा प्रदाता के रूप में स्पष्ट किया है।

उमरपुर के बड़का गांव में शनिचरा बाबा की पूजा में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

बक्सर (संवाददाता)। सदर प्रखंड के उमरपुर पंचायत अंतर्गत बड़का गांव मानसिंह पट्टी में शनिवार को शनिचरा बाबा की पूजा-अर्चना श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ आयोजित की गई। वार्षिक पूजा समारोह को लेकर गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही भक्तिमय माहौल बना रहा। शनिचरा बाबा के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आयोजन स्थल पर पहुंचे। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में मत्था टेककर सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की।

सुबह से ही बड़का गांव स्थित पूजा स्थल पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र भक्तों की भीड़ से भरता गया। श्रद्धालु विधि-विधान के साथ बाबा शनिचर की पूजा-अर्चना करते नजर आए। पूजा को लेकर ग्रामीणों में भी विशेष उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे पूजा समारोह में शामिल हुए और बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।

आयोजन समिति और ग्रामीणों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया। पूजा समारोह में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए ग्रामीण और आयोजन समिति से जुड़े लोग सक्रिय रहे। सामूहिक सहयोग से पूजा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और उत्सवी वातावरण में संपन्न हुआ।

शनिचरा बाबा की पूजा के अवसर पर मंदिर के समीप मेले का भी आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें सजाई गई थीं। खान-पान की दुकानों के साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए भी कई साधन उपलब्ध रहे। पूजा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने दर्शन के बाद मेले में खरीदारी की और परिवार के साथ मनोरंजन का आनंद लिया।

मेले में बच्चों की विशेष रुचि देखने को मिली। बच्चे अपने परिजनों के साथ मेले में घूमते नजर आए। वहीं बुजुर्ग और महिलाएं भी पूजा के बाद मेले में लगी दुकानों का आनंद लेते रहे। दूर-दराज के इलाकों से पहुंचे श्रद्धालुओं के कारण आयोजन स्थल पर पूरे दिन लोगों की आवाजाही बनी रही।

शनिचरा बाबा की पूजा के प्रति स्थानीय लोगों के साथ-साथ आसपास के गांवों के लोगों में भी आस्था देखने को मिली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़का गांव पहुंचे। श्रद्धालुओं ने बाबा शनिचर के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर अपने परिवार तथा समाज की सुख-शांति की कामना की। पूजा समारोह को लेकर गांव में पहले से ही उत्साह का माहौल था। ग्रामीणों ने आयोजन की तैयारियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पूजा स्थल की व्यवस्था से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा और मेले के आयोजन तक ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रही।

पूजा समारोह के अवसर पर आयोजन समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत दोगोला कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों और आसपास के लोगों में विशेष उत्सुकता बनी हुई है।

भक्तिमय माहौल में हुई शनिचरा बाबा की पूजा

शनिचरा बाबा की पूजा को लेकर बड़का गांव और आसपास के ग्रामीणों में काफी उत्साह रहा। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की और अपने परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। पूजा स्थल पर दिनभर धार्मिक माहौल बना रहा। बाबा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण पूरे आयोजन स्थल पर चहल-पहल बनी रही।

23 सितंबर को निकलेगी भगवान वामन की भव्य रथयात्रा

बक्सर (संवाददाता)। भगवान वामन की अवतार स्थली के रूप में प्रसिद्ध बक्सर में वामन द्वादशी के पावन अवसर पर आगामी 23 सितंबर को भगवान वामन चेतना मंच के तत्वावधान में भव्य रथयात्रा का आयोजन किया जाएगा। रथयात्रा को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए मंच के पदाधिकारी एवं सदस्य जोर-शोर से तैयारियों में जुटे हैं। आयोजन को लेकर नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है।

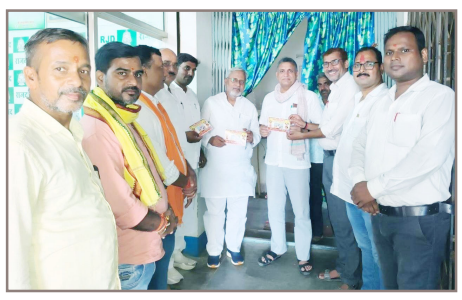

भगवान वामन चेतना मंच के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी एवं शाहाबाद प्रक्षेत्र के अध्यक्ष रिंकु पांडेय के नेतृत्व में मंच के सदस्य लगातार विभिन्न मोहल्लों और गांवों में पहुंचकर लोगों को रथयात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान मंच के सदस्य घर-घर जाकर आमंत्रण पत्र वितरित कर रहे हैं तथा अधिक से अधिक लोगों से इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बनने की अपील कर रहे हैं। आयोजित होने वाली भगवान वामन की भव्य रथयात्रा रामरेखा स्थित रामेश्वर नाथ मंदिर से प्रारंभ होगी। इसके बाद रथयात्रा नगर के विभिन्न मार्गों और प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेगी तथा अंत में वामन भगवान के मंदिर में पहुंचकर संपन्न होगी। रथयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत सनातनी समाज के लोगों के साथ-साथ महिलाओं, युवाओं, व्यवसायियों, जनप्रतिनिधियों एवं समाज के सभी वर्गों से रथयात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की जा रही है। आयोजकों का कहना है कि बक्सर की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़े इस आयोजन को व्यापक जनभागीदारी के साथ भव्य रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

रथयात्रा में शामिल होने के लिए सांसद सुधाकर सिंह, बक्सर सदर विधायक आनंद मिश्र तथा पूर्व विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी को भी आमंत्रित किया गया है। मंच के सदस्यों द्वारा लगातार जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न वर्गों के लोगों से संपर्क कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। भगवान वामन रथयात्रा को सफल बनाने के लिए मंच की ओर से लगातार बैठकें आयोजित कर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। रथयात्रा के मार्ग, जनभागीदारी, आमंत्रण अभियान सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर सदस्य सक्रियता से कार्य कर रहे हैं।

बक्सर के एमवी कॉलेज में भोजपुरी के संवैधानिक अधिकार पर हुआ सार्थक संवाद, भाषा की विरासत और पहचान को लेकर उठी मजबूत आवाज

बक्सर(संवाददाता)। जिले के महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय, बक्सर में भोजपुरी भाषा के संवैधानिक अधिकार, संरक्षण और संवर्धन को लेकर विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शब्दन फाउंडेशन एवं महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संवाद-श्रृंखला के अंतर्गत 'भोजपुरी के संवैधानिक अधिकार' विषय पर विशेष व्याख्यान हुआ। कार्यक्रम में जमानियां विधायक ओम प्रकाश सिंह, महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय के भोजपुरी विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय के प्राचार्य सहित कई गणमान्य लोग और अन्य साथी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी भाषा के संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ इसके संरक्षण, संवर्धन और समृद्ध भाषायी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। वक्ताओं ने भोजपुरी भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भोजपुरी केवल बातचीत और संवाद का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह मिट्टी, लोकजीवन, संस्कृति, परंपरा और करोड़ों लोगों की पहचान से गहराई से जुड़ी हुई भाषा है।

संवाद कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि भोजपुरी की अपनी विशिष्ट मिठास और शैली है, जिसमें लोकपरंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है। इसकी बोली में गांव-घर के जीवन, सामाजिक संबंधों और लोक संस्कृति की झलक मिलती है, जबकि इसके साहित्य में समाज की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को स्थान मिला है।

वक्ताओं के अनुसार भोजपुरी भाषा की सबसे बड़ी विशेषताओं में इसकी लोकधारा भी शामिल है। लोकगीतों, लोककथाओं, साहित्य, रंगमंच और सिनेमा के माध्यम से भोजपुरी ने लंबे समय से समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़े रखा है। भोजपुरी की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों ने देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ-साथ विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है। कार्यक्रम में भोजपुरी के लोकगीतों और साहित्य के महत्व पर भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि भोजपुरी लोकगीतों में आम जनजीवन, सामाजिक परंपराओं, पारिवारिक रिश्तों, पर्व-त्योहारों और ग्रामीण संस्कृति की जीवंत तस्वीर दिखाई देती है। इसी तरह भोजपुरी साहित्य ने समाज की भावनाओं और अनुभवों को शब्द देने का कार्य किया है।

रंगमंच और सिनेमा के क्षेत्र में भी भोजपुरी भाषा की अपनी विशिष्ट पहचान बनी है। भोजपुरी से जुड़े

सांस्कृतिक कार्यक्रमों और साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से भाषा की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार जारी है। वक्ताओं ने कहा कि भाषा की समृद्ध विरासत को केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित रखने के बजाय इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी है। संवाद के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि भोजपुरी भाषा और संस्कृति का प्रभाव भारत के बाहर भी देखने को मिलता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भोजपुरी भाषी समुदाय मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा है। लोकगीतों, पारिवारिक परंपराओं और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से विदेशों में रहने वाले भोजपुरी भाषी लोग भी अपनी भाषायी जड़ों से जुड़े हुए हैं। वक्ताओं ने कहा कि भोजपुरी की यह व्यापक सांस्कृतिक उपस्थिति इसकी समृद्ध विरासत को दर्शाती है। भाषा के प्रति लोगों की भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव को देखते हुए इसके संरक्षण और विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम में भोजपुरी को उचित सम्मान और संवैधानिक पहचान दिलाने से जुड़े विषय पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि किसी भी भाषा को मजबूत बनाने के लिए केवल सरकारी स्तर पर प्रयास पर्याप्त नहीं होते, बल्कि समाज, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, युवाओं और भाषा से जुड़े लोगों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक होती है। संवाद के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि भोजपुरी के संवैधानिक अधिकार और पहचान से जुड़े विषयों पर सामाजिक एवं बौद्धिक स्तर पर निरंतर चर्चा होनी चाहिए। इसके माध्यम से भाषा से जुड़े लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और भोजपुरी की समृद्ध परंपरा को सहेजने के लिए सामूहिक प्रयासों को गति मिलेगी।

वक्ताओं ने कहा कि भोजपुरी भाषा का संरक्षण केवल उसके बोलचाल तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके साथ भोजपुरी साहित्य, लोककला, लोकगीत, लोककथाओं, रंगमंच और अन्य सांस्कृतिक परंपराओं को भी सुरक्षित रखना जरूरी है। भाषा के साथ जुड़ी इन परंपराओं में समाज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मृतियां मौजूद हैं। यदि नई पीढ़ी अपनी भाषा और लोक परंपराओं से जुड़ी रहेगी, तभी भोजपुरी की सांस्कृतिक विरासत आगे बढ़ सकेगी। इसी कारण विद्यालयों और महाविद्यालयों में भोजपुरी भाषा और संस्कृति से जुड़े विषयों पर संवाद, कार्यक्रम और रचनात्मक गतिविधियां आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

कार्यक्रम में भोजपुरी भाषा के भविष्य को लेकर युवाओं की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि नई पीढ़ी किसी भी भाषा के संरक्षण और विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। युवाओं के बीच भोजपुरी भाषा, साहित्य और संस्कृति को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक मतिउर्रहमान द्वारा अजीमाबाद प्रिंटर्स, आर. सी. एफ./105, ग्राउण्ड फ्लोर, बी. एच. कॉलोनी, भूतनाथ रोड, कंकड़बाग, पटना- 800026 बिहार से मुद्रित एवं अमला टोली, मेन रोड़, बक्सर -802101, बिहार से प्रकाशित, संपादक- मतिउर्रहमान, E-mail:- qalamlok@gmail.com, Regn. No. BIHHIN/2017/72480